राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

DKU LIVE
सब पर नज़र, सबकी ख़बर

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

वर्ष – 04 | अंक – 63 | जौनपुर गुरूवार, 16 अक्टूबर 2025 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

शीर्ष कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

नई दिल्ली, (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें कांग्रेस विधायक के वाई नंजेगौड़ा की जीत को रद्द किया गया था। शीर्ष कोर्ट ने चुनाव आयोग को 2023 के मालुर विधानसभा क्षेत्र में मतगणना की दोबारा जांच कर रिपोर्ट बंद लिफाफे में कोर्ट में सौंपने का आदेश दिया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने नंजेगौड़ा को विधायक बने रहने की अनुमति दी।लेकिन हाईकोर्ट के 16 सितंबर के कुछ निर्देशों को बरकरार रखा। जिन्होंने नंजेगौड़ा के खिलाफ चुनाव लड़ा था और वोटों की गिनती में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाई जाती है, जिसमें नंजेगौड़ा का चुनाव रद्द किया गया था। इसके चलते वह विधायक बने रहेंगे। हालांकि, कोर्ट ने चुनाव आयोग को हाईकोर्ट के उस निर्देश का पालन करने को कहा जिसमें वोटों की दोबारा गणना की बात कही गई थी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मतगणना के बाद बिना कोर्ट की अनुमति के कोई परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। नंजेगौड़ा की तरफ से पेश वरिष्ठ वकीलअभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हाईकोर्ट ने सात मुद्दे तय किए, लेकिन किसी पर फैसला नहीं दिया।

चुनाव में धनबल के इस्तेमाल पर निर्वाचन आयोग सख्त

नई दिल्ली, (एजेंसी)। बिहार विधानसभा चुनाव और सात राज्यों की आठ विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग सख्त है। चुनाव के दौरान पैसों के दुरुपयोग और मतदाताओं को प्रभावित करने के प्रयासों पर रोक लगाने के लिए निर्वाचन आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में व्यय पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। जो उम्मीदवारों के चुनावी खर्च पर पैनी नजर रखेंगे। आगामी चुनावों में धनबल, मुफ्तखोरी के साथ–साथ नशीली दवाओं, नशीले पदार्थों और शराब के इस्तेमाल पर अंकुश लगाने के लिए आयोग ने दो चरणों में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों और 8 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों के लिए सभी प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश जारी किए हैं। एक बयान में चुनाव आयोग ने कहा कि उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले चुनावी खर्च की निगरानी के लिए व्यय पर्यवेक्षकों को पहले ही तैनात कर दिया गया है और वे चुनाव की अधिसूचना के दिन अपने–अपने निर्वाचन क्षेत्रों में पहुंच गए हैं। चुनाव आयोग ने कहा, अपने दौरे के दौरान वे व्यय निगरानी में लगी सभी टीमों से मिलेंगे। उड़न दस्ते, निगरानी दल, वीडियो निगरानी दल मतदाताओं को लुभाने के लिए धनबल या अन्य प्रलोभनों के किसी भी संदिग्ध मामले पर नजर रखने के लिए चौबीसों घंटे सतर्क रहेंगे। इसी के साथ चुनाव आयोग ने बताया कि चुनाव की घोषणा के बाद से विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों ने कुल 33.97 करोड़ रुपए की।

त्योहारों में शांति भंग करने वालों की जगह सिर्फ जेल में होगी - सीएम योगी

लखनऊ, (संवाददाता)। दीपावली के त्योहार में अब बस कुछ ही दिन बाकी है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को उपद्रवियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई भी त्योहार के आनंद और उत्साह को बाधित करने की कोशिश करेगा तो उसे बिना किसी देरी के सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी देते हुए कहा, "उत्साह और उमंग के त्योहार में किसी ने रंग में भंग डालने का काम किया, किसी ने व्यवधान डालने का प्रयास किया तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी। वो कोई भी होगा उसे अंदर ठूंसने में बहुत देर नहीं लगेगी। इसीलिए बहनों और भाइयों त्योहार शांतिपूर्ण तरीके और सौहार्दपूर्ण तरीके से एक दूसरे को बधाई देते हुए हमें मनाने चाहिए।" सीएम योगी ने आगे कहा, "मुझे

प्रसन्नता है कि गत आठ वर्ष के अंदर जो भी पर्व और त्योहार उत्तर प्रदेश में आयोजित हुए सारे के सारे समुदायों के चाहे वो होली हो या दीपावली हो या विजयादशमी, रामनवमी हो ईद या क्रिसमस का पर्व हो सारे के सारे त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित होते हैं। हर एक व्यक्ति अपने–अपने त्योहार को मनाएं। अपनी आस्था का सम्मान करें, ये पर्व और त्योहार सड़कों पर प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। ये सामूहिक रूप से अपनी अभिव्यक्ति को समाज के सामने प्रस्तुत करने का एक माध्यम होता है। लोग एक–दूसरे से गले मिलें और सामूहिक रूप से विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बनें। अपने परिवार की खुशी को अपने समाज के साथ शेयर करे। यही पर्व और त्योहार के पीछे का उद्देश्य होता है। अब ये वो भाव और सरकार नहीं है जो दंगाइयों के सामने घुटने टेकती हो। ये सरकार तो जो जिस भाषा में समझेगा, उस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाना भी जानती है।" मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, "2017 के पहले परिवार से ऊपर सोच ही नहीं थी। केवल अपने परिवार के बारे में सोचता था। महाभारत के सभी रिश्ते उसमें आते थे।

जेपी नड्डा ने कहा देश में नकली दवाओं पर लगेगी लगाम

नई दिल्ली, (एजेंसी)। मध्य प्रदेश में कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद केंद्र सरकार ने देश में घटिया और नकली दवाओं पर लगाम लगाने को लेकर निगरानी व्यवस्था सख्त करने का फैसला किया है। सरकार इस पर नया कानून लाने की तैयारी में है, जिससे दवाओं की गुणवत्ता, जांच और बाजार निगरानी को कानूनी मजबूती दी जा सके। सरकार इस विधेयक को संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश करने की योजना है। सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने की अध्यक्षता में स्वास्थ्य मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक में ड्रग कंट्रोलर डॉ. राजीव सिंह रघुवंशी ने 'दवा, चिकित्सा उपकरण और कॉस्मेटिक्स अधिनियम 2025' का मसौदा पेश किया। बैठक में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रस्तावित कानून की रूपरेखा रखी। सीडीएससीओ की 2023–24 की रिपोर्ट के अनुसार, जांच की गई करीब 5,500 दवाओं में से 3.2 प्रतिशत नमूने सबस्टैंडर्ड या नकली पाए गए। वहीं, पिछले दो वर्षों में 40 से अधिक फार्मा इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मध्य

प्रदेश की घटना से पहले हरियाणा, जम्मू–कश्मीर और तमिलनाडु में भी घटिया सिरप से बच्चों की मौत के मामले सामने आ चुके हैं। कई मामलों में डायथिलीन ग्लाइकॉल (डीईजी) नामक रसायन की मिलावट पाई गई। सूत्रों के मुताबिक, बिल के तहत पहली बार सीडीएससीओ को वैधानिक शक्तियां दी जाएंगी, ताकि नकली या घटिया दवाओं के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जा सके। इसके साथ ही लाइसेंसिंग प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल करने, राज्य स्तर के नियामकों के बीच बेहतर समन्वय, और प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ाने जैसे प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है ।

पीएम मोदी आंध्र प्रदेश को 13430 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को आंध्र प्रदेश का दौरा करेंगे, जहां वह 13,430 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मोदी राज्य के दौरे की शुरुआत श्रीशैलम स्थित श्री भ्रामराम्बा मल्लिकार्जुन स्वामी वरला देवस्थानम और श्री शिवाजी स्फूर्ति केंद्र से करेंगे। फिर कुरनूल में परियोजनाओं का अनावरण करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी अपनी यात्रा की शुरुआत श्री भ्रामराम्बा मल्लिकार्जुन स्वामी वरला देवस्थानम, श्रीशैलम से करेंगे। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों और 52 शक्तिपीठों में से एक है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, इस मंदिर की एक अनूठी विशेषता एक ही परिसर में एक ज्योतिर्लिंग और एक शक्ति पीठ का सह–अस्तित्व है, जो इसे पूरे देश में अपनी तरह का एक अनूठा मंदिर बनाता है। प्रधानमंत्री मंदिर में पूजा–अर्चना करने के बाद श्री शिवाजी स्फूर्ति केंद्र का भी

दौरा करेंगे, जो एक स्मारक परिसर है। यहां चार कोनों पर प्रतापगढ़, राजगढ़, रायगढ़ और शिवनेरी किलों के मॉडल बनाए गए हैं और केंद्र में एक ध्यान कक्ष है, जो शिवाजी महाराज की स्मृति को समर्पित है। श्रीशैलम दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी कुरनूल जाएंगे, जहां वे विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री उद्योग, बिजली पारेषण, सड़क, रेलवे, रक्षा विनिर्माण और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस आदि क्षेत्रों की परियोजनाओं की सौगात देंगे ।

रक्षा मंत्रालय ने पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए वित्तीय सहायता में 100 प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों और पूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए वित्तीय सहायता योजनाओं में 100 प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दी है। बुधवार को इस संबंध में जानकारी देते हुए रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये योजनाएं पूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा केन्द्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से लागू की जाती हैं। वित्तीय सहायता में की गई प्रमुख बढ़ोतरी इस के तहत अनुदान 4,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 8,000 रुपए प्रति माह प्रति लाभार्थी कर दिया गया है। यह सहायता 65 वर्ष से अधिक आयु वाले उन पूर्व सैनिकों के आश्रितों और विधवाओं को आजीवन दी जाएगी, जिनकी कोई नियमित आय नहीं है और जो गैर–पेंशनभोगी हैं। वहीं शैक्षणिक अनुदान 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपए प्रति माह प्रति विद्यार्थी कर दिया गया है। यह सहायता अधिकतम दो

आश्रित बच्चों को कक्षा 1 से स्नातक तक या दो वर्षीय परास्नातक कोर्स कर रही आश्रित विधवाओं को दी जाएगी। विवाह अनुदान में भी बढ़ोतरी की गई है। इसे 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए प्रति लाभार्थी कर दिया गया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह अनुदान अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह अथवा विधवा पुनर्विवाह के लिए लागू होगा, बशर्ते विवाह इस आदेश के जारी होने के बाद संपन्न हुआ हो। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि मंजूरी की गई नई दरें 1 नवंबर 2025 से प्राप्त आवेदनों पर लागू होंगी। इससे प्रति वर्ष लगभग 257 करोड़ रुपए का वित्तीय भार पड़ेगा, जो आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड से वहन किया जाएगा। ये सभी योजनाएं रक्षा मंत्री पूर्व सैनिक कल्याण कोष के तहत संचालित हैं, जो आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड का एक उप–कोष है। रक्षा मंत्रालय का मानना है कि इस निर्णय से गैर–पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों, विधवाओं और निम्न आय वर्ग के आश्रितों के लिए सामाजिक सुरक्षा तंत्र को और मजबूत किया गया है। यह कदम सरकार की उन प्रतिबद्धताओं को पुनरू स्थापित करता है जिनके तहत वह देश की सेवा और बलिदान देने वाले सैनिकों के सम्मान एवं कल्याण के लिए सतत प्रयासरत है।

राष्ट्रपति मुर्मू ने मंगोलियाई समकक्ष का स्वागत किया

नई दिल्ली, (एजेंसी)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना का राष्ट्रपति भवन में स्वागत किया और उनके सम्मान में रात्रिभोज आयोजित किया। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि भारत और मंगोलिया के बीच संबंधों को और मजबूत करने की काफी संभावना है, खासकर विकास सहयोग, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंधों के क्षेत्र में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को कहा कि भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को सहयोग के समकालीन आयामों को जोड़कर और विस्तारित करने का समय आ गया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने मंगोलियाई राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना और उनके प्रतिनिधिमंडल का

राष्ट्रपति भवन में स्वागत करते हुए कहा कि साझा सांस्कृतिक विरासत और लोकतांत्रिक मूल्य भारत–मंगोलिया संबंधों की नींव हैं। भारत और मंगोलिया रणनीतिक साझेदार, तीसरे पड़ोसी और आध्यात्मिक पड़ोसी हैं। भारत मंगोलिया के साथ विकास और क्षमता निर्माण साझेदारी को सर्वोच्च प्राथमिकता देता और मौजूदा परियोजनाओं को समय पर पूरा करने को प्रतिबद्ध है, जो भारत–मंगोलिया मैत्री और सहयोग के स्थायी प्रतीक के रूप में उभरेंगे। राष्ट्रपति भवन से जारी बयान के अनुसार, दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि अब समय आ गया है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तारित किया जाए और सहयोग के नए एवं समकालीन आयाम जोड़े जाएं, जिससे दोनों देशों के लोगों को लाभ होगा। राष्ट्रपति ने भरोसा जताया कि आज संपन्न सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम पर समझौता ज्ञापन सांस्कृतिक आदान–प्रदान को और बढ़ावा देने के लिए मजबूत आधार प्रदान करेगा। मंगोलियाई राष्ट्रपति उखना चार दिवसीय यात्रा पर दिल्ली में हैं। इससे पहले आज हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और मंगोलिया के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई, जहां दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापनों का आदान–प्रदान हुआ।

एकजुटता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत : जनरल द्विवेदी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों को मौजूदा वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए ज्यादा मजबूत, तेज और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने की बात पर जोर दिया। उन्होंने मंगलवार को कहा कि संयुक्त राष्ट्र (यूएन) शांति मिशनों को और ज्यादा मजबूत, तेज और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने की जरूरत है, ताकि बढ़ती चुनौतियों से बेहतर ढंग से निपटा जा सके। जनरल द्विवेदी ने ये बात भारत की मेजबानी में आयोजित यूएन शांति मिशन में योगदान देने वाले 32 देशों के सैन्य प्रमुखों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। इस दौरान उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अशांत वैश्विक हालात, गैर–राज्य संगठनों की बढ़ती भूमिका, हाइब्रिड युद्ध और गलत जानकारी (डिसइन्फॉर्मेशन) जैसे खतरे शांति अभियानों को और जटिल बना रहे हैं।जनरल द्विवेदी ने कहा कि आज की दुनिया 56 से ज्यादा सक्रिय संघर्षों और करीब 90 देशों की भागीदारी के कारण एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है। ऐसे समय में शांति सेना की एकजुटता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सेना प्रमुख ने यह भी कहा कि बदलते हालात के चलते अब तेज, एकजुट और टिकाऊ जवाब

देने की जरूरत है, जो केवल मिलकर काम करने वाले शांति सैनिक ही दे सकते हैं। उन्होंने भारत की यूएन शांति मिशनों में अहम भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि हमें उन्नत तकनीक को अभियान में शामिल करना होगा, त्वरित तैनाती की क्षमता बढ़ानी होगी। साथ ही सहयोग देने वाले देशों के बीच बेहतर तालमेल बनाना होगा। इसके साथ ही जनरल द्विवेदी ने यह भी सुझाव दिया ।

कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित करेंगी मायावती

लखनऊ, (संवाददाता)। बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के संस्थापक कांशीराम जी के 19वें परिनिर्वाण दिवस पर 16 अक्टूबर को बीएसपी यूपी स्टेट कार्यालय, 12 माल एवेन्यू लखनऊ में बैठक बुलाइ गई है। बैठक को बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष संबोधित करेंगी। इस दौरान वे संगठन की आगामी दिशा और रणनीति पर मार्गदर्शन देंगी। कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शुरू होगा। हुजन समाज पार्टी (बसपा) ने आगामी चुनावों से पहले संगठन में बड़ा बदलाव किया है। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने प्रदेशभर में नए सिरे से संगठन खड़ा करने की कवायद शुरू करते हुए मंडल स्तर पर दो–दो टीमें नियुक्त की हैं। एक मंडलीय कार्यों की जिम्मेदारी संभालेगी और दूसरी स्थानीय स्तर पर सक्रिय रहेगी। इन स्थानीय टीमों की निगरानी मंडलीय कोऑर्डिनेटर करेंगे और उनकी रिपोर्ट सीधे मायावती को भेजी जाएगी। बसपा सुप्रीमो 16 अक्टूबर को सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर संगठन विस्तार और भविष्य की रणनीति पर विस्तृत निर्देश देने वाली हैं। हालांकि, जिला, विधानसभा, सेक्टर और पोलिंग बूथ कमेटियों के ढांचे में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। मायावती चाहती हैं कि कांशीराम की पुण्यतिथि पर हुई रैली जैसी सफलता अब हर स्तर पर दिखाई दे। पार्टी के अंदर निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाया गया है और सक्रिय चेहरों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। लखनऊ मंडल में पूर्व सांसद धनश्याम चंद्र खरवार, सूरज सिंह जाटव, समसुद्दीन राइन, मौजी लाल गौतम और राकेश कुमार को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। पार्टी ने सामाजिक समीकरण मजबूत करने के लिए सभी जिलों में भाईचारा कमेटियों का भी पुनर्गठन किया है। इन कमेटियों में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा, वैश्य और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट के ग्रीन पटाखों पर फैसले का किया स्वागत

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पटाखों पर प्रतिबंध की शर्तों में ढील देने के फैसले का स्वागत किया, जिससे दिवाली पर दिल्ली–एनसीआर क्षेत्र में ग्रीन पटाखों की बिक्री और फोड़ने की अनुमति मिल गई। आभार व्यक्त करते हुए, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने इस फैसले को पर्यावरण संरक्षण और त्योहार की भावना के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण बताया। ग पर एक पोस्ट में, उन्होंने कहा कि हम दिल्ली सरकार के विशेष अनुरोध पर राजधानी में ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति देने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। यह फैसला दिवाली जैसे पवित्र त्योहारों के दौरान जनता की भावनाओं और उत्साह का सम्मान करता है, साथ ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति

एक संतुलित दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक ष्स्वच्छ और हरितष दिल्ली सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार जनभावनाओं का सम्मान करते हुए, स्वच्छ और हरित दिल्ली के संकल्प के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि त्योहारों की रौनक बरकरार रहे और साथ ही पर्यावरण की सुरक्षा भी हो। इस दिवाली, आइए हम सब मिलकर हरित पटाखे जलाएँ, उत्सव और पर्यावरण संरक्षण में सामंजस्य स्थापित करें और हरित एवं समृद्ध दिल्ली के संकल्प को साकार करने की दिशा में काम करें। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली में 18–20 अक्टूबर तक तीनों दिन सुबह 6 बजे से 7 बजे और रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ग्रीन पटाखे फोड़े जा सकेंगे। डिप्टी कमिश्नर निर्धारित स्थानों पर ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति देंगे। ग्रीन पटाखे ई–कॉमर्स चौनलों के माध्यम से नहीं बेचे जा सकेंगे। लाइसेंस प्राप्त पटाखा निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि दिल्ली–एनसीआर में केवल ग्रीन पटाखे ही बेचे जाएं। अगर कोई सामान्य पटाखे बेचते पकड़ा गया तो उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। सीपीसीबी, राज्य प्रदूषण बोर्ड के साथ मिलकर प्रदूषण और एक्यूआई रीडिंग की निगरानी करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए मानदंड निर्धारित किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिवाली से पहले दिल्ली–राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों पर प्रतिबंधा की शर्तों में ढील देते हुए ।

संपादकीय

आखिर समाधान क्या है?

कथित जातीय उत्पीड़न के मामले अक्सर सामने आते हैं। मामला शांत होने तक हर बार यही चर्चा होती है कि आज भी किस हद तक जातिगत भेदभाव फैला हुआ है। मगर ऐसी चर्चाएं कभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचतीं। हरियाणा कैडर के आईपीएस वाई. पूरन कुमार की आत्म–हत्या को संस्थागत जातीय उत्पीड़न की मिसाल बताया गया है। कुमार ने सात अक्टूबर को चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर आत्महत्या कर ली। अपने सुसाइड नोट में उन्होंने 15 वरिष्ठ अधिकारियों पर मानसिक उत्पीड़न और जातिगत भेदभाव के गंभीर आरोप लगाए। स्वाभाविक है कि मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। इसी समय मध्य प्रदेश की एक घटना भी सुर्खियों में है। इसके मुताबिक दमोह जिले में एक ओबीसी युवक को कथित रूप से जबरन एक ब्राह्मण व्यक्ति का पैर धोकर पानी पिलाया गया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद सामाजिक संगठनों ने वहां विरोध प्रदर्शन किया। ये घटनाएं कोई अजूबा नहीं हैं। अक्सर विभिन्न क्षेत्र के संस्थानों से लेकर गांव–देहात तक से कथित जातीय उत्पीड़न के मामले सामने आते रहते हैं। जब तक मामला शांत नहीं होता, उसको लेकर यही चर्चा होती है कि भारतीय समाज में आज भी जातिवाद और जातिगत भेदभाव फैला हुआ है। मगर ऐसी चर्चाएं कभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचतीं। कुछ जातियों को उत्पीड़क बता कर या सदियों से मौजूद जातीय उत्पीड़न की चर्चा कर इंसाफ के पैरोकार आगे बढ़ जाते हैं। वे यह सवाल नहीं उठाते कि सौ–डेढ़ सौ साल से इसी तरह का विमर्श जारी रहने, संविधान में तमाम भेदभाव खत्म करने के स्पष्ट प्रावधान होने और साढ़े तीन दशक से सामाजिक न्याय की राजनीति के हावी रहने के बावजूद हालात क्यों नहीं बदले हैं? ये कठिन और असहज करने वाले प्रश्न हैं। इनकी तह में जाने पर नजर आएगा कि खुद किस तरह जातिगत पहचान और प्रतिनिधित्व को सामाजिक न्याय का पर्याय बना कर इसके पैरोकारों ने सारा विमर्श जातिवाद पर केंद्रित कर दिया है। इससे वंचित समूहों के बीच व्यापक एकता और समाज के आधुनिकीकरण की संभावनाएं क्षीण हो गई हैं। नतीजतन, जाति के विनाश का वह लक्ष्य पीछे छूट गया है, जिसे केंद्र में रखकर आधुनिक भारत के निर्माण की परियोजना शुरू की गई थी। इससे कुछ नेता–परिवारों और मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों को अवश्य लाभ हुआ है, मगर जातिवाद या जमीनी स्तर पर जातीय भेदभाव को खत्म करने का मार्ग और बाधित ही हुआ है।

तालिबानी अब हमारे सखा है

श्रुति व्यास

कुछ दिनों से भारत में एक ही खबर है! और वह एक तालिबानी के दौरे की है। बाकी सब कुछ, चाहे बिहार चुनाव हो, सीट बँटवारे की जोड़–बाकि, या गाजा में युद्धविराम की खबर, सब साइडलाइन पर खिसक गए हैं। दिल्ली का फोकस केवल तालिबान पर केंद्रित है। और यह सिफ जिज्ञासा नहीं है। हाँ, उन्हें चलते, बोलते, कैमरे के सामने सहज होते देखना एक तमाशे जैसा है, लेकिन तालिबान प्रतिनिधिमंडल खुद भी जानता है कि यह ध्यान उनके काम आता है। भारत में यह उनका मौका है कृ दिखने, सुने जाने और शायद थोड़ा घूमने–फिरने का भी। इस पूरे सप्ताह के नजारे के केंद्र में हैं आमिर खान मुत्ताकधी, तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री। वही मुत्ताकधी जिनकी यात्रा पर अब भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 1988 के तहत आंतकी के नाते पाबंदी है, वे अब दिल्ली के झूमरों के नीचे तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। यह उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है, लेकिन 2021 में पद संभालने के बाद उनकी दसवीं विदेश यात्रा। उनमें से पाँच कध्तर, तीन पाकिस्तान, और दो–दो चीन, ईरान और तुर्की के लिए थीं। अब दिल्ली भी उस सूची में शामिल हो गया है। और दिल्ली से उनका जुड़ना प्रतीकात्मक से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। 10 अक्टूबर को मुत्ताकधी ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकधत की, भारत द्वारा अफगानिस्तान भेजी जा रही एम्बुलेंसों के साथ तस्वीरें खिंचवाईं, और काबुल में भारतीय दूतावास फिर से खोलने पर चर्चा की जो चार साल पहले तालिबान की सत्ता वापसी के बाद बंद कर दिया गया था। मुत्ताकधी के मुँह से अच्छे दोस्त और जयशंकर के बयान में करीबी सहयोग जैसे शब्द दर्शाते हैं कि भारत की नीति में यह बदलाव संयोग नहीं, सुविचारित है। चार साल पहले तक यह सब असंभव लगता था। 2021 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से वापसी की समयसीमा तय की, तो दिल्ली स्तब्ध थी। 15 अगस्त को काबुल पर तालिबान के कब्जे ने भारत को रातों–रात दूतावास और वाणिज्य दूतावास बंद करने पर मजबूर कर दिया। हजारों अफगान छात्र, व्यापारी और मरीज अचानक फँस गए। भारत ने एक झटके में लगभग सभी वीजा रद्द कर दिए। वह क्लिक आतंक और पलायन दोनों का प्रतीक था। लेकिन कूटनीति, जैसे शक्ति, खालीपन को बर्दाश्त नहीं करती। सिफ एक साल में भारत ने फिर से संतुलन साधना शुरू किया। जून 2022 में एक तकनीकी दल चुपचाप काबुल भेजा गया ताकि मानवीय सहायता की निगरानी कर सके। 2023 के अंत तक तालिबान अधिकारियों को भारतीय वीजा मिलने लगे, दिल्ली में उनके प्रतिनिधि नियुक्त हुए और मुंबई व हैदराबाद में वाणिज्य दूतावास खुले। जो संपर्क मानवीय कहलाया था, वह धीरे–धीरे औपचारिक संवाद में बदल गया। यह परोपकार नहीं, रणनीतिक समायोजन था कृ यह स्वीकारोक्ति कि तालिबान कोई गुजरती लहर नहीं बल्कि इस क्षेत्र की नई और स्थायी वास्तविकता है। और अगर दिल्ली पीछे रहती, तो चीन, ईरान और रूस अफगानिस्तान के अगले अध्याय को उसके बिना लिख देते। यहाँ एक गहरी विडंबना भी है। एक हिंदू राष्ट्रवादी सरकार, जो अपने भीतर सभ्यतागत विमर्श और इस्लाम के प्रति अविश्वास पर टिकी है, अब अपने पड़ोस में एक इस्लामी थियोक्रेसी के साथ बैठी है। जिस नेतृत्व की वैचारिक पहचान भीतर विरोध पर टिकी है, उसके लिए तालिबान का दिल्ली में स्वागत एक साथ विरोधाभास भी है और व्यावहारिकता भी। क्योंकि विदेश नीति शायद ही कभी घरेलू राजनीति की परछाई होती है। भारत इस समय जिस नीति का अभ्यास कर रहा है, वह अंतरराष्ट्रीय संबंधों की क्लासिक यथार्थवादी धारा है कृ रियलिज्म कृ जिसे हांस मॉर्गेन्थाउ और केनेथ वाल्ट्ज ने परिभाषित किया थारू राष्ट्र आदर्शों से नहीं, हितों से चलते हैं। इस दुनिया में न स्थायी दोस्त होते हैं, न स्थायी दुश्मन कृ सिफ स्थायी बेचैनियाँ। भले ही भाजपा की सांस्कृतिक राजनीति धार्मिक द्वंद्व पर चलती है, उसकी विदेश नीति इन सीमाओं से काफी आगे निकल चुकी है। यह ऑफेंसिव रियलिज्म है कृ सिद्धांतों से ऊपर शक्ति, निष्ठा से ऊपर लाभ। तालिबान के साथ संवाद और अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य वापसी के खध्लिाफ भारत का अप्रत्यक्ष रुख, उसे रूस, ईरान और चीन द्वारा परिभाषित महाद्वीपीय सहमति के निकट ला रहा है कृ वह क्षेत्रीय यथार्थवाद जो अमेरिका–उत्तर युग का चेहरा बन रहा है।

इस्राइल-हमास युद्धविरामः आशा की किरण या अस्थायी विराम

ललित

गाजा की धरती लम्बे दौर से संघर्ष, हिंसा, विनाश और तबाही की त्रासदी की गवाह रही है, आज फिर एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहाँ शांति की एक हल्की किरण दिखाई तो देती है, परंतु उसके चारों ओर धुएँ और राख का अंधकार अब भी विद्यमान है। हाल ही में हुए युद्ध–विराम ने न केवल मध्यपूर्व बल्कि समूचे विश्व को राहत की एक साँस दी है। गाजा में अमन–चौन की ओर जो सुखद कदम बढ़े हैं, उनका स्वागत होना चाहिए। परंतु यह सवाल भी उतना ही प्रासंगिक है कि क्या यह शांति स्थायी होगी, या यह केवल अगली लड़ाई से पहले का ठहराव भर है? समूची दुनिया चाहती है कि यह युद्ध विराम स्थायी हो क्योंकि इस्राइल और हमास के संघर्ष ने करीब बाइस लाख से अधिक लोगों को बेघर करके भुखमरी के कगार पर पहुंचा दिया है। ऐसे में दोनों पक्षों के लिये समझौते के पहले चरण को पूरी तरह से लागू करना बेहद जरूरी होगा। जिसमें बंधकों व कैदियों की रिहाई, गाजा में मानवीय सहायता को अनवरत जारी रखना और इस्राइली सेनाओं की गाजा के मुख्य शहरों से आंशिक वापसी सुनिश्चित करना भी शामिल है। यह सब दूसरे चरण की बातचीत पर निर्भर हैं। यदि सब कुछ ठीक–ठाक रहा तो इसके बाद ही दूसरे चरण की बातचीत की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। यह बेहद मुश्किल चुनौतियों वाला चरण होगा। इस दौरान कई संवेदनशील मुद्दे सामने होंगे। सबकी निगाह इस पर होगी कि शांति समझौते के अगले चरण कब पूरे होते हैं और वे सही तरह पूरे होते भी हैं या नहीं? इस पर संशय इसलिए है, क्योंकि यह स्पष्ट नहीं कि इजरायली सेना गाजा में कितना पीछे हटेगी और वहां के प्रशासन को संचालित करने का कैसा तंत्र तैयार होगा और क्या उस पर हमास सहमत होगा? इसके अतिरिक्त जहां हमास को हथियार छोड़ने हैं, वहीं इजरायल को स्वतंत्र फिलस्तीन देश की राह आसान करनी है। हमास का कहना है कि हथियार तब छोड़े जाएंगे, जब स्वतंत्र फिलस्तीन का रास्ता साफ होगा। इस पर इजरायल तैयार नहीं दिख रहा है। यह ठीक है कि स्वयं की ओर से प्रस्तावित गाजा शांति समझौते पर अमल शुरू होने के अवसर पर मिस्र जाने के पहले इजरायल पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी पहल को पश्चिम एशिया में शांति की स्थापना का पथ करार दिया और इजरायली प्रधानमंत्री से ईरान से समझौता करने को कहा। ऐसे किसी समझौते की सूरत तब बनेगी, जब ईरान इजरायल को मिटाने की अपनी जिद छोड़ेगा। गाजा की वर्तमान स्थिति किसी एक राष्ट्र या एक नीति की देन नहीं हैय यह दशकों से चली आ रही अविश्वास, असमानता और राजनीतिक स्वार्थों की परिणति है। इस बार के संघर्ष ने जिस तरह से निर्दोष नागरिकों, बच्चों और महिलाओं को अपना शिकार बनाया, उसने यह स्पष्ट कर दिया कि युद्ध चाहे किसी भी नाम पर लड़ा जाए, उसका परिणाम हमेशा मानवीय त्रासदी ही होता है। अस्पताल, विद्यालय, धार्मिक स्थल–कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं रहा। अमेरिकी मध्यस्थता वाले युद्धविराम समझौते के बाद हमास ने आखिरकार शेष जीवित बचे बीस इस्राइली बंधकों को रिहा कर दिया। जिसके बाद इस्राइल में किसी बड़े उत्सव जैसा जश्न दिखा। बहरहाल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अभी भी इस्राइल–हमास जोखिमभरा युद्धविराम समझौता नाजुक बना हुआ है। इसकी वास्तविक परीक्षा आने वाले दिनों में होगी। इस संघर्षरत क्षेत्र में स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिये जरूरी है कि प्रमुख हितधारकों की ओर से गंभीर एवं ईमानदार प्रयास लगातार होते रहें। वर्तमान समय में सबसे बड़ी चुनौती भूतहा खण्डहर एवं तबाही में तब्दील हो चुके गाजा के पुनर्निर्माण की होगी। दो साल से लगातार जारी युद्ध के चलते यह इलाका मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। एक नाजुक समय में जब युद्धविराम की घोषणा हुई, तो यह केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं है, बल्कि मानवीय विवेक का पुनर्जागरण भी है। यह समझना आवश्यक है कि शांति कोई समझौता नहीं, बल्कि एक अनिवार्य आवश्यकता है। यही कारण है कि यह युद्धविराम पूरी मानवता के लिए एक 'आशा की किरण' बनकर उभरा है। यह उस संभावना का प्रतीक है कि जब दुनिया के शक्तिशाली देश, विशेषकर अमेरिका, यूरोप, और अरब राष्ट्र अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं से ऊपर उठकर मानवीय सरोकारों को महत्व देते हैं, तो समाधान की दिशा में रास्ता बनता है। फिर भी इस शांति की वास्तविकता पर प्रश्नचिह्न बने हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही इस युद्धविराम को अपने कूटनीतिक प्रयासों की उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया हो, पर सच यह है कि युद्ध तब रुका जब उसकी भयावहता अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुकी थी। यह विराम किसी की "कूटनीति की जीत" से अधिक, मानवीय विवशता की उपज है। अंतरराष्ट्रीय दबाव, मानवीय संगठनों की सक्रियता और आम नागरिकों की पुकार ने मिलकर इस विराम को संभव बनाया। अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि यह शांति टिके, युद्ध का अंधेरा नहीं, शांति का उजाला फैले। क्योंकि जब तक गाजा के लोगों को जीवन की मूलभूत सुविधाएँ–पानी, भोजन, दवा, शिक्षा और सम्मानजनक जीवन नहीं मिलते, तब तक शांति केवल कागजों पर दर्ज रहेगी। वास्तविक शांति केवल तब संभव है जब अन्याय, दमन और असमानता

के ढाँचे टूटें। शांति का अर्थ केवल हथियारों का मौन नहीं, बल्कि हृदयों का परिवर्तन है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजरायली संसद को संबोधित करते हुए गाजा शांति समझौते को पश्चिम एशिया की ऐतिहासिक सुबह की संज्ञा दी। वे कुछ भी दावा करें, फिलहाल यह कहना कठिन है कि प्रमुख मुस्लिम देश इजरायल को मान्यता देने के लिए तैयार होंगे। भले ही ट्रंप यह कह रहे हों कि गाजा शांति समझौते को सभी मुस्लिम देशों का समर्थन मिला, लेकिन वस्तुस्थिति इससे अलग है। जब यह समझौता सामने आया था, तब उसे समर्थन देने और ट्रंप की प्रशंसा करने वालों में पाकिस्तान भी था, पर अब वह इस समझौते को समर्थन देने से केवल पीछे ही नहीं हट गया, बल्कि उसने अपने यहां ऐसा माहौल बनाया कि उसके विरोध में कट्टरपंथी तत्व सड़क पर उतर आए। यह मानने के अच्छे–भले कारण हैं कि पाकिस्तान ने गाजा शांति समझौते को नकारने के लिए ही कट्टरपंथी तत्वों को सड़कों पर उतरने के लिए उकसाया और फिर उन पर गोलियां भी चलवाईं, ताकि दुनिया और विशेष रूप से अमेरिका को यह संदेश जाए कि उसके लिए गाजा शांति समझौते को स्वीकार करना संभव नहीं। यहां अमेरिका को पाक के दोहरे चरित्र को समझ लेना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, अरब लीग और विश्व की सभी बड़ी शक्तियों की जिम्मेदारी है कि वे इस युद्धविराम को केवल घोषणा भर न रहने दें। उसे स्थायी बनाने के लिए एक ठोस मानवीय पुनर्निर्माण योजना तैयार की जाए, जिसमें राजनीतिक समाधान, मानवीय सहायता और संवाद–तीनों को समान महत्व मिले। गाजा के बच्चे जब फिर से स्कूलों में लौटेंगे, जब शरणार्थी अपने घरों में बस सकेंगे, जब भय की जगह भरोसा जन्म लेगा, तभी यह कहा जा सकेगा कि गाजा में शांति आई है।

विश्वास का वैश्विक सेतु और व्यापारिक समरसता का आधार

ललित

विश्व मानक दिवस प्रत्येक वर्ष 14 अक्तूबर को मनाया जाता है। यह दिवस उस अदृश्य व्यवस्था का उत्सव है जो हमारे जीवन, उद्योग, व्यापार और सुरक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करती है। मानकीकरण केवल कोई तकनीकी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह

विश्वसनीयता, सुरक्षा, पारदर्शिता और आपसी सहयोग की ऐसी बुनियाद है जो मानव जीवन की सहजता और स्थिरता का आधार बनती है। इस दिवस का उद्देश्य यह स्मरण कराना है कि किसी भी उत्पाद, सेवा या व्यवस्था की उपयोगिता तभी टिकाऊ और भरोसेमंद हो सकती है जब उसमें निर्धारित मानक और गुणवत्ता की कसौटी कायम हो। विश्व मानक दिवस उन हजारों विशेषज्ञों और कर्मयोगियों को सम्मान देने का भी अवसर है जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में बैठकर विश्व के हित में ऐसे मानक तय करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के निर्माण और कार्यान्वयन में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सुरक्षा के साथ–साथ जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मानकीकरण की भूमिका पर जोर देना है, जो सबके लिए समान हों, निष्पक्ष हों और मानवता की सुरक्षा और प्रगति के लिए हों। यह दिवस 1946 में हुई पहली बैठक की याद में मनाया जाता है, जिसमें 25 देशों के प्रतिनिधि लंदन में एक अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना के लिए एकत्र हुए थे, जो मानकीकरण पर अपने प्रयासों को केंद्रित करेगा। हालाँकि अगले वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन का गठन किया गया था, लेकिन पहला विश्व मानक दिवस 1970 में ही मनाया गया। विश्व मानक दिवस का उद्देश्य जनता को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मानकों की महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति जागरूक करना है। अर्थात् स्वास्थ्य सेवा से लेकर तकनीक तक, लगभग हर क्षेत्र के उत्पादों और सेवाओं में सुरक्षा, विश्वसनीयता और गुणवत्ता। 2025 की थीम 'सहयोग' है, जो प्रगति को संभव बनाने के लिए साझेदारी के महत्व को दर्शाती है। यह सहयोग की शक्ति और इस विश्वास का प्रमाण है कि हम अपने–अपने हिस्सों के योग से भी अधिक शक्तिशाली हैं। साथ मिलकर काम करके, हम लोगों को स्थिरता की चुनौतियों का सीधा सामना करने के लिए वास्तविक समाधानों से सशक्त बना रहे हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय मानक ब्यूरो ने इस वर्ष की थीम को 'सतत विकास लक्ष्यः लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी' के रूप रखा है। एक बेहतर विश्व निर्माण के लिए साझा दृष्टिकोण का विशेष महत्व है, इस दिवस को मनाने का लक्ष्य उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान देना और उपभोक्ताओं, नियामकों और उद्योग के बीच मानकीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। आज जब वैश्वीकरण, तकनीकी तीव्रता, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य संकट और आपूर्ति श्रृंखला जैसी जटिल चुनौतियाँ सामने हैं, तब मानकीकरण का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। मानक ही वह भाषा हैं जिनसे विश्व के देश एक–दूसरे को समझ पाते हैं। जब कोई वस्तु या सेवा एक निश्चित मानक के अनुरूप होती है, तो उसे किसी भी देश में स्वीकार किया जा सकता है। इससे व्यापार सहज होता है, उपभोक्ता का भरोसा बढ़ता है और देशों के बीच परस्पर निर्भरता मजबूत होती है। यही कारण है कि मानकीकरण को विश्व व्यापार की आत्मा कहा जाता है। इससे केवल आर्थिक लाभ नहीं होता, बल्कि यह जीवन की गुणवत्ता, सुरक्षा और पर्यावरणीय संतुलन को भी सुनिश्चित करता है। विश्व मानक दिवस के इस सन्देश के विपरीत आज की राजनीति में कई बार ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जो विश्व व्यापार और आपसी सहयोग की भावना को कमजोर करते हैं। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा अपनाई जा रही अतिशयोक्ति पूर्ण टैरिफ नीति इसका उदाहरण है। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रतिस्पर्धा के नाम पर आयातित वस्तुओं पर भारी शुल्क लगाकर एक प्रकार से व्यापार युद्ध का वातावरण बना दिया है। यह नीति केवल व्यापारिक हितों को नहीं बल्कि वैश्विक संतुलन को भी प्रभावित कर रही है। टैरिफ की यह दीवारें देशों के बीच अविश्वास बढ़ाती हैं, कीमतों में वृद्धि करती हैं और आपूर्ति श्रृंखला को असंतुलित करती हैं। आयातित वस्तुओं की लागत बढ़ने से उपभोक्ताओं को अधिक कीमत चुकानी पड़ती है, उद्योगों की उत्पादन लागत बढ़ती है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार की गति धीमी पड़ जाती है। विश्व व्यापार संगठन ने पहले ही चेताया है कि ऐसी टैरिफ नीतियाँ वैश्विक व्यापार वृद्धि को घटा रही हैं और निवेशकों में अस्थिरता पैदा कर रही हैं। टैरिफ केवल कर या शुल्क नहीं होते, वे राष्ट्रों के बीच विश्वास का संकेत भी होते हैं। जब कोई देश बार–बार अपने आर्थिक हितों की आड़ में ऊँचे शुल्क लगाता है, तो अन्य राष्ट्र प्रतिकार के रूप में अपने दरवाजे बंद करने लगते हैं। परिणाम यह होता है कि जो विश्व पहले एक साझा बाजार की ओर बढ़ रहा था, वह फिर से सीमाओं और अविश्वास की जंजीरों में बँधने लगता है। ऐसे में विश्व मानक दिवस यह सन्देश देता है कि दुनिया को जोड़ने का वास्तविक माध्यम व्यापारिक शुल्क नहीं बल्कि मानकीकरण है। मानक देशों को एक साझा धरातल प्रदान करते हैं, जहाँ उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा का विश्वास इतना मजबूत होता है कि किसी अतिरिक्त शुल्क या रोक की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मानकीकरण दरअसल विश्वास का पुल है जो सीमाओं के आर–पार लोगों, वस्तुओं और विचारों को जोड़ता है। जब एक देश दूसरे देश के मानकों को स्वीकार करता है, तो यह आपसी सम्मान और पारदर्शिता का प्रतीक होता है। इसी प्रक्रिया से अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सरलता आती है, सुरक्षा और गुणवत्ता की गारंटी मिलती है और उपभोक्ता हित सुरक्षित रहते हैं। मानकीकरण की यह प्रक्रिया न केवल औद्योगिक या व्यापारिक है बल्कि यह मानवीय भी है। इसके मूल में समानता, निष्पक्षता और सहयोग की भावना निहित है। यह वह दर्शन है जो कहता है कि विश्व एक परिवार है और सबकी भलाई में ही अपनी भलाई है। अतः जब कोई राष्ट्र टैरिफ या प्रतिबंधों की दीवार खड़ी करता है,।

युद्ध और शांति के खेल में नोबेल

निरज

वैश्विक राजनीति में किस तरह नोबेल पुरस्कार जैसे प्रतिष्ठित सम्मान की आड़ में नए खेल रचे जा रहे हैं, इसका ताजा उदाहरण 2025 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए घोषित नाम पर सामने आया। वेनेजुएला की राजनेता मारिया कोरिना मचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। समिति ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार शांति के एक साहसी और ऐसी चौंपियन को दिया जाता है, जो बढ़ते अंधकार के बीच लोकतंत्र की लौ को जलाए रखती है।बता दें कि मारिया कोरिना मचाडो को वेनेजुएला की श्आयरन लेडीश भी कहा जाता है, उन्होंने स्वतंत्र चुनावों को बढ़ावा देने वाले नागरिक समाज समूह सुमाते और लोकतांत्रिक परिवर्तन की वकालत करने वाले गठबंधन सोयवेनेजुएला की स्थापना में सहायता की। वे 2010–2015 से नेशनल असेंबली की सदस्य रही हैं। बताया जाता है कि पिछले कुछ सालों में मारिया को छिपकर रहना पड़ा था, क्योंकि उनकी जान को खतरा था, लेकिन वो देश छोड़कर नहीं गईं। नोबेल समिति का कहना है कि वेनेजुएला में रहना उनका फैसला था, जिससे कई लोगों को प्रेरणा मिली। जब तानाशाह सत्ता पर कब्जा कर लेते हैं, तो स्वतंत्रता के लिए लड़ने और सत्ता का विरोध करने वाले लोगों को पहचानना जरूरी होता है।लेकिन यही पूरा सच नहीं है। न ही मचाडो दुनिया में अकेली ऐसी नेता हैं। दुनिया के कई देशों में सत्ता की मनमानी और लोकतंत्र के नाम पर तानाशाही को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति के खिलाफ आवाजें उठाई जा रही हैं, सत्ता के दमन और अत्याचारों का सामना किया जा रहा है। मचाडो अगर लोकतंत्र के लिए संघर्ष करती रही हैं, तो दूसरी तरफ वे युद्ध के तरीकों की हिमायत भी करती रही हैं। खासकर इजरायल की वे समर्थक रही हैं। गजा पर बमबारी को वो इजरायल का सही फैसला मानती हैं। साथ ही मारिया अपने खुद के देश में सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए विदेशी ताकतों की मदद लेने से भी नहीं कतराती हैं। 2018 में उन्होंने इजरायल और अर्जेंटीना को खत लिखकर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पद से हटाने की अपील की थी। 2 साल पहले अपनी एक पोस्ट में मारिया ने लिखा था कि श्वेनेजुएला का संघर्ष भी इजरायल की तरह है।श मारिया ने यहां तक कहा था कि अगर वो सत्ता में आईं तो इजरायल की आजादी में पूरी मदद करेंगी।ऐसे में सहज ही सवाल उठता है कि जिस इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर युद्ध के आरोप हों, जिनकी बर्बरता पिछले दो सालों में दुनिया ने देखी है, उसका समर्थन करने वाला कोई भी शख्स आखिर किस तरह नोबेल शांति पुरस्कार का हकदार हो सकता है। लोकतंत्र की बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी करते हैं, बल्कि वे तो दुनिया में सात ऐसे युद्धों को बंद करवाने का दावा करते हैं, जिनके खत्म होने की संभावनाएं नहीं थीं और वे जारी रहते तो भीषण तबाही होती। भारत और पाकिस्तान के बीच जंग रोकने का दावा भी कम से कम 40 बार ट्रंप कर चुके हैं, जिसे पाकिस्तान ने तो माना है, भारत ने इससे इंकार किया है। हालांकि फिर भी ट्रंप को झूठा कहने की हिम्मत नरेन्द्र मोदी ने अब नहीं दिखाई है। बहरहाल, इन युद्धों को रुकवाने की वजह से ट्रंप खुद को शांति पुरस्कार का सबसे बड़ा दावेदार मान चुके थे। कई बार इसका सार्वजनिक इजहार उन्होंने किया। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने बाकायदा कहा कि वे ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने की सिफारिश करते हैं। फिर गजा शांति समझौते के बाद जिस तरह अमेरिका समर्थक तमाम देशों ने ट्रंप की वाहवाही के ट्वीट किए, उससे जाहिर हुआ कि नोबेल शांति पुरस्कार के लिए जमकर गुटबंदी हो रही है। हालांकि मचाडो को पुरस्कार मिलने की घोषणा के बाद ट्रंप की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। लेकिन मचाडो ने इस पुरस्कार को ट्रंप को समर्पित करने के साथ ही संकेत दे दिए कि अभी वैश्विक राजनीति में युद्ध और शांति के खेल की लंबी पारी उन्हें खेलनी है।इस बीच गजा शांति समझौते के बाद सोमवार को जब इजरायल और हमास के बीच कैदियों का आदान–प्रदान होना था, तब डोनाल्ड ट्रंप इजरायल पहुंच चुके थे। यहां उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। इस दौरान ट्रंप ने इजरायल और हमास के समझौते को अपनी श्आठवीं हल की गई संघर्षश उपलब्धि बताया और यह भी कहा कि मैंने ये सब नोबेल के लिए नहीं किया। यहां ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान का जिक्र भी किया कि अगर ये दोनों देश फिर युद्ध की ओर बढ़े, तो मैं टैरिफ लगाऊंगा। यह वही पुरानी धमकी है, जो मई में भी ट्रंप ने दी थी। तो मचाडो हों या ट्रंप, इनका इतिहास और वर्तमान यही सुझा रहा है कि दोनों ही शांति पुरस्कार के सही हकदार नहीं थे। ट्रंप को तो खैर नोबेल पुरस्कार मिला ही नहीं, लेकिम मचाडो को देने से क्या पुरस्कार की गरिमा कम हुई है, यह सवाल वैश्विक पटल पर उभरा है। अमेरिका स्थित मुस्लिम अधिकारों के लिए बने संगठन काउंसिल ऑन अमेरिकन–इस्लामिक रिलेशन ने नोबल समिति को अपने फैसले पर फिर से विचार करने का सुझाव दिया है। संगठन का कहना है, श्नोबल समिति को एक बार फिर से सोचना चाहिए। मारिया को यह पुरस्कार देने से नोबल की छवि को गहरा झटका लग सकता है।श वैसे मारिया कोरिनो मचाडो को पुरस्कार मिलने के साथ ही अमेरिका और रूस फिर आमने–सामने दिख रहे हैं। दरअसल मारिया को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन है, वहीं, वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को पुतिन का साथ मिला हुआ है।

75% उपस्थिति जरूरी, विद्यार्थी रोज न आए तो घर पर करें फोन - राज्यपाल

लखनऊ, (संवाददाता)। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में बेहतर शैक्षिक गुणवत्ता के लिए विद्यार्थियों की 75: उपस्थिति अनिवार्य है। ऐसा नहीं होने पर विद्यार्थी परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे। यदि कोई विद्यार्थी अनुपस्थित है तो उसके घर पर फोन किया जाए। ताकि अभिभावक को भी पता चल सके कि उनका बच्चा कहां है। मौका था मंगलवार को ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह का। राज्यपाल ने शिक्षकों से भी कहा कि वे भी अनुशासन का पालन करें। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय में डीजी लॉकर पर डिग्री अपलोड करते हुए कहा कि एक समय था जब विद्यार्थी को अपनी ही डिग्री की कॉपी लेने के लिए विश्वविद्यालय में दो–दो हजार घूस देनी पड़ती थी। आज ये सब बंद है और विद्यार्थियों को राहत है। इससे पहले कुलपति प्रो. अजय तनेजा ने विवि की प्रगति के बारे में बताया। कार्यक्रम में इस साल स्नातक, परास्नातक और पीएचडी के कुल 1441 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जिनमें 1393 सफल हुए। छात्राओं का पास प्रतिशत 97.4 और छात्रों का 96.8 फीसदी रहा। इस साल समारोह में कुल 146 पदक दिए गए। इनमें 63 स्वर्ण, 42 रजत और 41 कांस्य पदक हैं। 99 पदक छात्राओं को मिले हैं। बता दें कि यहां 21 राज्य और छह धर्मों के विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। अल्लू नगर डिगुरिया प्राथमिक विद्यालय के बच्चों ने पेड़ों की रक्षा का संदेश देते हुए कार्यक्रम प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि फिल्मकार मुजफ्फर अली ने विद्यार्थियों से कहा कि पढ़ाई के लिए दो चीजें अहम हैं संतुलन और मानवता। इन दो के बिना पढ़ाई बेकार है। भाषा बेहद अहम है। भाषा एक जमाने से दूसरे जमाने को जोड़ती है। उन्होंने अपनी पुस्तक श्जिक्रश्श की चर्चा करते हुए कहा कि उनमें लोगों से मुलाकात के दौरान निकलकर आई बातें और उनकी विशेषता की चर्चा है। छात्रा रहमाना ने बताया कि नियमित पढ़ें और लक्ष्य पर ध्यान दें तो सफलता मिलेगी। उर्दू, अरबी फारसी, कला एवं मानविकी संकाय और बीए उर्दू में प्रथम आने पर मुझे तीन स्वर्ण पदक मिले हैं। पिता इजहार सिद्दीकी फैशन डिजाइनर और मां सुमैया गृहिणी हैं। मेरा सपना है विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनना है। छात्र अपूर्व द्विवेदी ने बताया कि माता के नाम को ध्यान में रखते हुए पढ़ें सफलता मिलेगी। अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय और बीटेक में प्रथम आने पर मुझे तीन स्वर्ण पदक मिले हैं। आईआईटी से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूं। पिता हरिकेश द्विवेदी शिक्षक और मां सरोज गृहिणी हैं। इंजीनियर बनना मेरा सपना है। छात्र धर्मेश यादव के अनुसार एक अच्छा अध्यापक बनने के लिए विषय पर मजबूत पकड़ होना जरूरी है। स्नातक स्तर पर सभी संकाय में प्रथम, विज्ञान संकाय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने व बीएससी–रसायन में प्रथम आने पर तीन स्वर्ण पदक मिलें हैं । पिता बृजकिशोर यादव किसान और मां मनोरमा देवी गृहिणी हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर बनना सपना है। छात्रा तनु प्रिया ने बताया कि पहले अपने बेहतर कॅरिअर के लिए मन से पढ़ें। स्नातक में सामाजिक विज्ञान, बीएड में पहला स्थान मिलने पर दो स्वर्ण पदक मिलें हैं।

राममंदिर निर्माण की तरह कृष्ण जन्मभूमि मामले में मेरी भूमिका रहेगी

लखनऊ, (संवाददाता)। तुलसी पीठाधीश्वर जगद्गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज मंगलवार देर रात अयोध्या पहुंचे। यहां उन्होंने भगवान रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन–पूजन किया। दर्शन के बाद उन्होंने कहा कि रामलला के दर्शन कर मन आनंद से भर गया और ऐसा लगा मानो प्रभु स्वयं कह रहे हों "अस मन होय उठाए लेव कोरबा।" इस दौरान उन्होंने मथुरा को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा कि जैसे अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में उनकी भूमिका रही, वैसे ही अब कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। अयोध्या प्रवास के दौरान रामभद्राचार्य ने राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि यह मित्रों का सुखद मिलन रहा। महंत नृत्य गोपाल दास अब बहुत कम लोगों को पहचानते

हैं, लेकिन उन्होंने मुझे पहचान लिया, यह मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह में 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर उन्होंने कहा कि यह पूरे देश के लिए गौरव की बात है। दीपोत्सव पर उन्होंने कहा कि इस बार भी यह उत्सव भव्य और दिव्य होगा। तीन नए रिकॉर्ड भी बनाए जाएंगे।

संक्षिप्त खबरें

राम जन्मभूमि आंदोलन में भाग नहीं लेने वालों को बना दिया ट्रस्टी

लखनऊ, (संवाददाता)। चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य महाराज ने कहा कि अजीब विडंबना है, जिन्होंने एक बार भी राम जन्मभूमि आंदोलन में भाग नहीं लिया, उन्हें ही मंदिर का ट्रस्टी बना दिया गया। वह मंगलवार को विजेथुआ महावीरन धाम में वाल्मीकि रामायण कथा सुना रहे थे। रामभद्राचार्य महाराज ने कहा कि संतों ने गांव में जाना छोड़ दिया तो विसंगतियां बढ़ने लगीं। अवध और अवधी दोनों मुझे बहुत भाती हैं। यह मेरी और मेरे आराध्य की जन्मभूमि है। उन्होंने कहा कि सभी सनातनियों को मस्तक पर तिलक जरूर लगाना चाहिए। तिलक लगाने के अनेक फायदे हैं। तिलक के बिना ब्राह्मण यमराज जैसा दिखता है। वशिष्ठ के समझाने के बाद दशरथ ने राम–लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेजा। विश्वामित्र ने राम को विद्या प्रदान की। श्रीराम ने सबसे पहला वध ताड़का का किया।

नौकरानी ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी चोरी

लखनऊ, (संवाददाता)। विकासनगर के सेक्टर–7 में माहिन खान के घर नौकरानी शाहजहां ने प्रेमी फैजान और उसके दो दोस्तों फहीम व साकिब के साथ मिलकर चोरी की थी। पुलिस ने मंगलवार को नौकरानी व तीन अन्य को गिरफ्तार किया। एसीपी गाजीपुर ए विक्रम सिंह ने बताया कि आरोपी जानकीपुरम के मड़ियांव गांव के रहने वाले हैं। माहिन ने छह अक्तूबर को मुकदमा लिखाया था। डिलीवरी बॉय बनकर आए अज्ञात पर नौकरानी को बेहोश करके चोरी का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने 150 फुटेज खंगालने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से चोरी किया जेवर भी बरामद कर लिया गया है।

गुज्जर गैंग का मेला में उत्पात, पुलिस से की मारपीट, दरोगा की कार तोड़ी

लखनऊ, (संवाददाता)। क्षेत्र के बिंदौआ गांव में सोमवार रात धार्मिक स्थल पर लगे मेले में अश्लील गाने पर डांस की फरमाइश पूरी न होने पर गुज्जर गैंग ने उत्पात मचाया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो युवक उनसे भी भिड़ गए और मारपीट शुरू कर दी। दरोगा की कार तोड़ दी। पांच युवकों को गिरफ्तार किया गया है। एसीपी मोहनलालगंज रजनीश वर्मा ने बताया कि रात 12 बजे गांव में ही रहने वाला गुज्जर गैंग का सरगना ललित रावत शराब के नशे में मंच पर चढ़ा और अश्लील गाने पर डांस की फरमाइश करने लगा। मौजूद पुलिसकर्मी उसे मंच से उतारकर थाने लाने लगे तो ललित के गैंग के 15–20 युवकों ने घेर लिया। इसी बीच किसी ने बिजली काट दी। अंधेरा होते ही गैंग ने पुलिस से मारपीट शुरू कर दी। ललित को पुलिस से छुड़वा लिया और दरोगा की कार का शीशा तोड़ दिया। मेले में अचानक हुई घटना से अफरातफरी मच गई। लोग भागने लगे तो आरोपियों ने एसयूवी तिरछी खड़ी कर रास्ता बंद कर दिया। इसके बाद जो सामने आया उसे पीटा। बवाल की सूचना पर भारी संख्या में पुलिस पहुंची और ललित, सदाशिव, मिथुन रावत, देश दीपक व विक्रांत कुमार को पकड़कर थाने ले गई।

आर्यमान को हराकर अनुज क्वार्टर फाइनल में

लखनऊ, (संवाददाता)। गैरवरीय उत्तर प्रदेश के अनुज कुमार ने आइटा सुपर सीरीज अंडर–18 टेनिस टूर्नामेंट में उलटफेर भरी जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसी के साथ पांचवीं वरीय उत्तर प्रदेश के अनुरुद्ध कुमार, छठीं वरीय राघव प्रभु, तीसरी वरीय ऋषि यादव व सानिध्य द्विवेदी ने भी अंतिम आठ में जगह बना ली। बालिका एकल में महाराष्ट्र की शिरीमोयी कामत ने छठीं वरीय दिल्ली की रूहिन कौशल के खिलाफ 6–4, 4–6, 6–2 से उलटफेर भरी जीत दर्ज की। उत्तर प्रदेश की मिराया अग्रवाल ने जीत से अंतिम आठ में जगह बनाई, जबकि उत्तर प्रदेश की ताशी किरण, आइरा, रमिंदर दीप कौर व अनुषा सिंह को हार का सामना करना पड़ा। ला–मार्टीनियर टेनिस फैसिलिटी में आयोजित टूर्नामेंट के बालक एकल के प्री क्वार्टर फाइनल में गैर वरीय उत्तर प्रदेश के अनुज कुमार ने कोर्ट पर दमदार खेल दिखाया और चौथी वरीय उत्तर प्रदेश के आर्यमान चव्हाण को 6–3, 6–4 से हराकर बाहर कर दिया। दूसरी ओर पांचवीं वरीय उत्तर प्रदेश के अनुरुद्ध कुमार ने उत्तर प्रदेश के हर्ष सिंह को 6–3, 3–6, 7–5, छठीं वरीय उत्तर प्रदेश के राघव प्रभु ने महाराष्ट्र के शौर्य बिराजदार को 6–1, 6–3, तीसरी वरीय उत्तर प्रदेश के ऋषि यादव ने दिल्ली के कनिष्क तोमर को 6–1, 6–3 और आठवीं वरीय उत्तर प्रदेश के सानिध्य द्विवेदी ने उत्तर प्रदेश के वंशराज जलोटा को 6–1, 6–2 से पराजित किया। इसके अलावा शीर्ष वरीय हरियाणा के हर्ष मलिक ने उत्तर प्रदेश के अंश सक्सेना को 6–0, 6–1 और हरियाणा के यज मलिक ने उत्तर प्रदेश के मो. शीज को 7–6(3), 6–3 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। बालक एकल में छठीं वरीय उत्तर प्रदेश के राघव प्रभु ने महाराष्ट्र के शौर्य बिराजदार को 6–1, 6–3, तीसरी वरीय उत्तर प्रदेश के ऋषि यादव ने दिल्ली के कनिष्क तोमर को 6–1, 6–3 और आठवीं वरीय उत्तर प्रदेश के सानिध्य डी.द्विवेदी ने वंशराज जलोटा को 6–1, 6–2 से हराया। बालिका एकल के प्री क्वार्टर फाइनल में शीर्ष वरीय दिल्ली की स्नेह नंदल ने महाराष्ट्र की दिया मनोज अग्रवाल को 6–3, 4–6, 7–5 और महाराष्ट्र की शिरीमोयी कामत ने छठीं वरीय दिल्ली की रूहिन कौशल को 6–4, 4–6, 6–2 से हराकर उलटफेर किया। यूपी की आशी शमशेरी ने द्वितीय वरीय दिल्ली की मानवी राठी को 6–4, 0–6, 6–2 से हराया, वहीं सातवीं वरीय उत्तर प्रदेश की मिराया अग्रवाल ने प्रदेश की ही अनुषा सिंह को 6–0, 6–0 से हराया। चौथी वरीय दिल्ली की द्युति जैन ने उत्तर प्रदेश की ताशी किरण को 6–0, 6–0, दिल्ली की मेहर शर्मा ने उत्तर प्रदेश की आइरा को 6–0, 6–1 और तीसरी वरीय दिल्ली की वैष्णवी सिंह ने उत्तर प्रदेश की रमिंदर दीप कौर को 6–0, 6–1 से पराजित किया।

गोहत्या कानून के दुरुपयोग पर यूपी पुलिस को हाईकोर्ट की फटकार

लखनऊ, (संवाददाता)। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश गोहत्या निवारण अधिनियम, 1955 के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा मामले दर्ज करने के लापरवाह तरीके पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार के शीर्ष अधिकारियों को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि स्पष्ट न्यायिक फैसलों के बावजूद ऐसे मामले क्यों जारी हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 7 नवंबर को तय की है। न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन और न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ ने प्रमुख सचिव (गृह) और पुलिस महानिदेशक को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अधीन न होने के बावजूद ऐसी एफआईआर क्यों दर्ज की जा रही हैं? कोर्ट ने राहुल यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। राहुल ने प्रतापगढ़ में गोहत्या अधिनियम की धारा 3, 5ए और 8 तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11 के तहत अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का आग्रह किया था। राहुल यादव ने दलील दी कि उनका ड्राइवर गाड़ी लेकर वापस नहीं

लौटा और बाद में उन्हें पता चला कि गाड़ी को नौ गोवंशों के साथ जब्त कर लिया गया है, जिन्हें कथित तौर पर वध के लिए ले जाया जा रहा था। उन्होंने कहा कि इस अपराध में उनकी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन पुलिस उन्हें परेशान कर रही है। पीठ ने कहा कि एफआईआर से यह पता चलता है कि पशु जीवित पाए गए थे और ऐसा कोई आरोप नहीं है कि उन्हें राज्य से बाहर ले जाया जा रहा था। पीठ ने यह भी कहा कि गोहत्या अधिनियम की धारा 5ए केवल अंतरराज्यीय परिवहन पर लागू होती है। इसी प्रकार किसी भी प्रकार के वध या अपंगता का आरोप नहीं लगाया गया था, इसलिए धारा 3 और 8 लागू नहीं होतीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि चूंकि, याचिकाकर्ता न तो वाहन का चालक था और न ही वाहन में मौजूद था, इसलिए पशु क्रूरता अधिनियम के प्रावधान प्रथम दृष्टया लागू नहीं होते। आदेश में खंडपीठ ने कोर्ट में आने वाली उन याचिकाओं की भारी संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की, जिनमें व्यक्तियों को गोहत्या अधिनियम के तहत झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है, जबकि इनमें किसी भी प्रकार का वध, चोट या अंतरराज्यीय परिवहन शामिल नहीं है।

संक्षिप्त खबरें

अमौसी ओवर ब्रिज पर अश्वयल टैंकर खड़ा करने वाले 495 अभियुक्तों के हुए चालान

लखनऊ, (संवाददाता)। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के समक्ष डीसीपी, ट्रैफिक की ओर से हलफनामा दाखिल कर बताया गया है कि अमौसी ओवर ब्रिज पर गैर कानूनी तरीके से ऑयल टैंकरों को खड़ा करने के मामले में अब तक 495 अभियुक्तों के चालान किए जा चुके हैं। साथ ही 118 ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है जो यह कृत्य बार–बार कर रहे हैं। डीसीपी ने अपने शपथ पत्र में यह भी कहा है कि इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी ऑयल कंपनियों की भी जिम्मेदारी है कि वे इन ऑयल टैंकर्स के मूवमेंट को समुचित तरीके से व्यवस्थित करें। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 नवंबर की तिथि नियत की है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति राजीव भारती की खंडपीठ ने शिव मोहन की जनहित याचिका पर दिया। याचिका में कहा गया है कि अमौसी ओवर ब्रिज पर गैर कानूनी तरीके से ऑयर टैंकर पार्क होते हैं जिनसे न सिर्फ ट्रैफिक की असुविधा होती है, बल्कि खतरा भी पैदा हो रहा है।

छठ की तैयारियां तेज, चला सफाई अभियान

लखनऊ, (संवाददाता)। छठ महापर्व की तैयारियां तेज हो गई हैं। भोजपुरी समाज छठ महापर्व 27 और 28 अक्तूबर को लक्ष्मण मेला मैदान में इस बार भी धूमधाम से मनाया जाएगा। इसे लेकर गोमती किनारे घाट पर सफाई अभियान शुरू हो गया है। मंगलवार को महापौर सुषमा खर्कवाल और भाजपा नेता नीरज सिंह ने भी पहुंचकर श्रमदान किया। भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभुनाथ राय ने बताया कि मंगलवार को सफाई अभियान में अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के वेद प्रकाश राय, सुरेश कुशवाहा, अवधेश, अंगदराम ओझा, संतोष बनारसी और केंद्रीय उत्पादन शुल्क के अपर आयुक्त उग्रसेन धर द्विवेदी समेत सैकड़ों लोगों ने श्रमदान किया। प्रभुनाथ राय ने बताया कि 27 अक्तूबर को शाम चार बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, ऊर्जा मंत्री एसके शर्मा, राज्यसभा सांसद अमर पाल मौर्य और महापौर सुषमा खर्कवाल समेत अन्य लोग मौजूद रहेंगे। इस दौरान सुप्रसिद्ध लोकगायिका कल्पना पटवारी (असम), गोपाल राय (बलिया) और सुरेश शुक्ला (मुंबई) समेत 200 लोक कलाकार 18 घंटे लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देंगे।

आईआईएम के समर प्लेसमेंट पैकेज में 16 फीसदी की बढ़ोतरी

लखनऊ, (संवाददाता)। भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) लखनऊ ने एक बार फिर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से सफलता की नई मिसाल कायम की है। इस बार 2025दृ2027 बैच के लिए संस्थान के प्रतिष्ठित स्नातकोत्तर प्रबंधन कार्यक्रम (पीजीपी) और कृषि व्यवसाय प्रबंधन कार्यक्रम के छात्रों के लिए आयोजित ग्रीष्मकालीन प्लेसमेंट प्रक्रिया में 580 से अधिक ऑफर मिले। आईआईएम लखनऊ ने मंगलवार को अपनी समर प्लेसमेंट रिपोर्ट जारी कर दी। इसके मुताबिक समर प्लेसमेंट के औसत मानदेय में करीब 16 फीसदी बढ़ोतरी हुई है। आईआईएम लखनऊ में इस साल प्लेसमेंट में शानदार बढ़त दर्ज की गई। उच्चतम घरेलू मानदेय 3.95 लाख रुपये प्रति माह रहा। उच्चतम अंतरराष्ट्रीय मानदेय 2.5 लाख रुपये प्रति माह रहा।

उत्तर प्रदेश में दीपावली एवं छठ पर्व के दौरान परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ करने के निर्देश

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दयाशंकर सिंह ने आगामी दीपावली एवं छठ पर्व (18 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2025 तक) के अवसर पर प्रदेशवासियों को उनके गंतव्य तक सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने अधिकारियों को अधिक से अधिक बसें संचालित करने और स्थानीय व मुख्य मार्गों पर सुव्यवस्थित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए सतर्क रहने के लिए कहा।मंत्री ने कहा कि पूर्वांचल में छठ पर्व बड़े पैमाने पर मनाया जाता है और इस दौरान महानगरों में रहने वाले लोग अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। दिल्ली से पूर्वी उत्तर प्रदेश, लखनऊ और कानपुर नगरों के लिए अधिक संख्या में बसें संचालित की जाएँ। यदि पूर्वी क्षेत्रों से गाजियाबाद, दिल्ली एवं पश्चिमी क्षेत्रों के लिए 60 प्रतिशत से अधिक लोड फैक्टर मिलता है, तो अतिरिक्त सेवाओं का संचालन किया जाएगा। भैयादूज के अवसर पर स्थानीय और आसपास के जनपदों में आवागमन बढ़ जाता है, इसलिए क्षेत्रीय अधिकारी स्थानीय स्तर पर प्रबंध सुनिश्चित करेंगे। परिवहन मंत्री ने निर्देश दिए कि निगम की बसों को शत–प्रतिशत ऑन रोड रखा जाए और उनके स्पेयर पार्ट्स, असेम्बली व मरम्मत की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। किसी भी दशा में अनफिट बसों का संचालन नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों का अवकाश प्रोत्साहन अवधि में सीमित रखने तथा ड्यूटी रोस्टर पद्धति से लागू करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही बस स्टेशनों और बसों में सफाई, पीने के पानी, बैठने की सुविधा, डिजिटल समय सारिणी और सहायता केंद्र की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने को कहा गया।अनुबद्धित बसों के स्वामियों को निर्देशित किया गया कि बसों का संचालन सुनिश्चित करने हेतु मरम्मत समय पर करवाई जाए। प्रवर्तन दल क्षेत्रों में जाकर बसों का निरीक्षण करेंगे और चालकों एवं परिचालकों का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट कर सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करेंगे।प्रबंध निदेशक परिवहन श्री प्रभु नारायण सिंह ने कहा कि परिवहन मंत्री के निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रोत्साहन अवधि में चालकोंध्परिचालकों एवं कार्मिकों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन ने आयोजित किया ''शिक्षामित्र के भविष्य निर्धारण'' कार्यशाला

लखनऊ, (संवाददाता)। आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में विधानसभा मुख्य भवन, तिलक हाल सभागार में ''शिक्षामित्र के भविष्य निर्धारण'' विषयक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में श्रम एवं सेवायोजन मंत्री, श्री अनिल राजभर जी उपस्थित रहे।कार्यक्रम की शुरुआत आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष श्री अमरेंद्र दुबे ने मंत्री जी का माला पहनाकर स्वागत एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर की और शिक्षामित्रों की समस्याओं एवं अपेक्षाओं से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि 5 सितंबर 2025 को शिक्षक दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री ने शिक्षामित्रों को आशीर्वाद दिया और उनके मानदेय वृद्धि एवं अन्य सुविधाओं की बात कही। अब प्रदेश भर के शिक्षामित्र इस आशीर्वाद के कार्यान्वयन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।श्रद्धेय मंत्री श्री अनिल राजभर ने शिक्षामित्रों को विश्वास दिलाया कि सरकार उनके संघर्ष को स्वीकार करती है और बहुत जल्द उनका प्रयास सार्थक रूप लेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षामित्र प्रदेश के दूरदराज के गांवों में प्राथमिक विद्यालयों में मेहनत और निष्ठा से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, इसलिए उनके भविष्य का उचित निर्धारण सरकार की प्राथमिकता है। मंत्री ने शिक्षामित्रों से अपील की कि वे समय पर विद्यालय में उपस्थित होकर अपने दायित्वों का पालन करें और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें।कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष श्री हरीकिशोर तिवारी ने की, जबकि संचालन शारदा कुमार शुक्ला ने किया।

उत्तर प्रदेश में पोषण माह के अवसर पर ''पोषण पाठशाला'' का आयोजन

लखनऊ, (संवाददाता)। पोषण माह के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग (आईसीडीएस) द्वारा ''पोषण पाठशाला'' का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों और किशोरों में बढ़ते मोटापे और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम हेतु संतुलित आहार और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देना था।अपर मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रीमती लीना जौहरी ने कहा कि बच्चों में बढ़ता मोटापा एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बनता जा रहा है। उन्होंने जनपद स्तरीय अधिकारियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और अभिभावकों से आग्रह किया कि वे बच्चों की भोजन आदतों पर विशेष ध्यान दें और उन्हें संतुलित, विविध और पौष्टिक आहार के महत्व से परिचित कराएँ। श्रीमती जौहरी ने बताया कि परिवार ही बच्चों के स्वस्थ भोजन व्यवहार का पहला विद्यालय है, इसलिए माता–पिता को स्वयं आदर्श प्रस्तुत करते हुए बच्चों को सही आहार और जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए।आईसीडीएस निदेशक, श्रीमती सरनीत कौर ब्रोका ने कहा कि ''पोषण पाठशाला'' का केंद्र बिंदु स्वस्थ जीवनशैली और संतुलित आहार का प्रचार–प्रसार है। उन्होंने राष्ट्रीय सर्वेक्षणों और कार्यक्रम आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि बच्चों में मोटापे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों पर प्रभाव डालती है। उन्होंने सुझाव दिया कि जिला स्तर पर ऐसे जागरूकता कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाएँ।कार्यक्रम में वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. पियाली भट्टाचार्य (एसजीपीजीआईएमएस, लखनऊ) ने ''स्वस्थ जीवनशैली और संतुलित आहार'' विषय पर विस्तृत प्रस्तुति दी।

2047 महाभियान में जनसामान्य से प्राप्त सुझावों और फीडबैक की प्रक्रिया जारी

लखनऊ, (संवाददाता)। समर्थ उत्तर प्रदेश–विकसित उत्तर प्रदेशध2047रू समृद्धि का शताब्दी पर्व महाभियान के अंतर्गत प्रदेश के 75 जनपदों में नोडल अधिकारियों एवं प्रबुद्ध जनों द्वारा छात्रों, शिक्षकों, व्यवसायियों, उद्यमियों, कृषकों, स्वयंसेवी संगठनों, श्रमिक संगठनों, मीडिया और आम जनमानस के साथ संवाद किया गया। इस दौरान प्रदेश की विगत आठ वर्षों की विकास यात्रा पर विस्तृत जानकारी दी गई और विकास हेतु रोडमैप पर चर्चा कर जनता से फीडबैक प्राप्त किया गया।नियोजन विभाग के अनुसार, विकसित पोर्टल के माध्यम से अब तक कुल 39,38,788 सुझाव प्राप्त हुए हैं। इनमें से 30,73,436 सुझाव ग्रामीण क्षेत्रों से और 8,65,352 सुझाव नगरीय क्षेत्रों से आए हैं। सुझावों का आयु वर्ग अनुसार विवरण इस प्रकार हैरू 31 वर्ष से कम आयु वर्ग से 19,02,153, 31–60 वर्ष आयु वर्ग से 18,42,962 और 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग से 1,93,674 सुझाव प्राप्त हुए हैं। सुझावों में कृषि, पशुधन और डेरी, उद्योग, आईटी और टेक्नोलॉजी, पर्यटन, ग्रामीण विकास, इन्फ्रास्ट्रक्चर, समाज कल्याण, नगरीय विकास एवं स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा जैसे विविध क्षेत्र शामिल हैं।जनपदों के अनुसार प्राप्त फीडबैक में संभल, जौनपुर, बिजनौर, गोरखपुर और सोनभद्र अग्रणी हैं, जबकि फिरोजाबाद, महोबा, फतेहपुर, इटावा और पीलीभीत से न्यूनतम सुझाव प्राप्त हुए। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जनसामान्य की भागीदारी और उनकी सक्रियता में अंतर है।लखनऊ से प्राप्त सुझावों में सुश्री रेखा शुक्ला ने कृषि और ग्रामीण उद्यमों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कोल्ड स्टोरेज क्रांति की दिशा में ब्लॉक स्तर पर विकेन्द्रित, सौर–ऊर्जा आधारित कोल्ड स्टोरेज के निर्माण, एग्रो प्रोसेसिंग, मिनी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और वन ग्राम पंचायत वन प्रोडक्ट की अवधारणा के माध्यम से किसानों के उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग को बढ़ावा देने का सुझाव दिया। उनके अनुसार इससे किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य और लाभ मिलेगा तथा ग्रामीण क्षेत्र की समृद्धि में योगदान होगा।भदोही से प्राप्त सुझावों में श्री प्रिन्स पाण्डेय ने ग्रामीण औद्योगिक विकास के लिए युवाओं और महिलाओं को प्रशिक्षण देने, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग जैसे सिलाई, बेकरी, पैकिंग और फर्नीचर यूनिट स्थापित करने, खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने, हथकरघा उद्योग में बुनकरों को आधुनिक डिजाइन और ऑनलाइन मार्केट से जोड़ने और कृषि आधारित उद्योगों तथा महिला हस्तशिल्प को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बेचने का प्रस्ताव रखा। इसके साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि स्थानीय ग्राम प्रधानों को प्रशिक्षित कर योजना के क्रियान्वयन में मार्गदर्शक बनाया जाए और पूंजी व सब्सिडी के लिए उपलब्ध योजनाओं का उपयोग कर स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जाए।सिद्धार्थनगर से सुश्री सरिता श्रीवास्तव ने सुझाव दिया कि गर्भवती महिलाओं को नियमित पोषण दिया जाए ताकि आने वाले बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना न करना पड़े। उन्होंने गांवों में टीकाकरण के नियमित अभियान की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मोबाइल उपयोग में सहूलियत सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही उन्होंने 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की सुचारू व्यवस्था करने की आवश्यकता जताई, जिससे प्रत्येक बच्चे की शिक्षा की नींव मजबूत हो सके।महाभियान के अंतर्गत जनसामान्य को जागरूक करने और सुझाव प्राप्त करने हेतु नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत स्तर पर बैठकों, सम्मेलन और गोष्ठियों का आयोजन किया गया। अब तक 153 नगर पालिकाओं और 6 नगर निगमों, 51 जिला पंचायतों, 365 नगर पंचायतों, 541 क्षेत्र पंचायतों और 36,137 ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम सम्पन्न हुए हैं। इन आयोजनों के माध्यम से स्थानीय नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और संबंधित विभागों के बीच संवाद–सम्पर्क को सशक्त किया गया।प्रदेश सरकार द्वारा प्राप्त सुझावों और फीडबैक के आधार पर विजन डॉक्यूमेंट्स का निर्माण जारी है। इस प्रक्रिया के माध्यम से 2047 तक विकसित और समृद्ध उत्तर प्रदेश की परिकल्पना को साकार किया जाएगा। सरकार का यह प्रयास सामूहिक भागीदारी और समन्वित विकास को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिससे प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की आकांक्षाओं और जरूरतों का ध्यान रखा जा सके।

डिजिटल आभा की चकाचौंध से चमकेगी रामनगरी,राम की पैड़ी पर 26 लाख दीप जलाकर अयोध्या रचेगी नया विश्व रिकॉर्ड

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।इस बार नौवें दीपोत्सव 2025 में अयोध्या केवल दीपों से ही नहीं, बल्कि डिजिटल आभा से भी जगमगाएगी।इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अयोध्या को विश्व के सांस्कृतिक मानचित्र पर डिजिटल और आध्यात्मिक नगरी के रूप में स्थापित करने की तैयारी अंतिम चरण में है।रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद तकनीक और संस्कृति का अद्भुत संगम पेश करेगा। धर्मपथ से लेकर लता चौक, रामकथा पार्क और सरयू घाट तक हर कोना रोशनी की अद्भुत छटा से नहाया रहेगा। इस संबंध में कार्य संस्था कंपनी के साइट इंचार्ज व डिजाइन मैनेजर नितिन कुमार ने बताया कि उन्हें प्रकाश व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई है।धर्मपथ पर नेशनल हाईवे से प्रवेश द्वार तक दोनों ओर 18–18 फीट ऊंचे 30 डिजिटल पिलर लगाए जा रहे हैं।इन स्तंभों पर रामायण के प्रसंगों की झलकियां और डिजिटल लाइट शो प्रदर्शित होंगे। यह डिजिटल प्रस्तुति 18 से 20 अक्टूबर तक चलेगी, जिससे श्रद्धालु स्वयं को त्रेता युग के दिव्य अनुभव में महसूस करेंगे।अयोध्या के प्रमुख स्थलों पर होगी भव्य लाइटिंग होंगी।रामकथा पार्क, राम की पैड़ी, हनुमानगढ़ी, बिरला मंदिर, तुलसी उद्यान, भजन संध्या स्थल और सरयू ब्रिज तक को सजाने–संवारने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है।संस्था द्वारा लगाए जा रहे आर्च गेट्स और डिजिटल पिलर्स अयोध्या की सड़कों को आधुनिक स्वरूप देंगे, वहीं धार्मिक भावना को भी जीवंत रखेंगे।इस बार राम की पैड़ी समेत 56 घाटों पर 26 लाख 11 हजार 101 दीपों से दीपोत्सव का विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है। हर दीप भगवान राम के आदर्शों और अयोध्या की दिव्यता का प्रतीक बनेगा।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं दीपोत्सव की तैयारियों पर लगातार नजर रखे हुए हैं। उनका स्पष्ट निर्देश है कि इस बार दीपोत्सव ऐसा हो जो अयोध्या की परंपरा, पर्यटन और तकनीक तीनों का संदेश विश्वभर में दे सके। सीएम योगी के नेतृत्व में दीपोत्सव न केवल धर्म और संस्कृति का उत्सव बनेगा, बल्कि यह "नवभारत की नई अयोध्या" का परिचायक भी होगा। दीपों की रोशनी और डिजिटल तकनीक का यह संगम अयोध्या को विश्व के पर्यटन मानचित्र पर और सशक्त बनाएगा। श्रद्धालु जहां दिव्य राममंदिर का दर्शन करेंगे, वहीं डिजिटल प्रस्तुति के माध्यम से रामायण के अद्भुत प्रसंगों का अनुभव करेंगे।

आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही परीक्षा कार्यक्रम जारी किए जाएंगे : परीक्षा नियंत्रक

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय प्रशासन सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन कराने की तैयारी में जुटा है। आवेदन के लिए वेबसाइट 17 अक्टूबर से सक्रिय होने की संभावना है। विश्वविद्यालय नवंबर के दूसरे सप्ताह से सेमेस्टर परीक्षाएं शुरू कराने की तैयारी कर रहा है।इस संबंध में गुरुवार को जानकारी देते हुए परीक्षा नियंत्रक डॉ. विनोद कुमार सिंह ने बताया कि परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया इसी सप्ताह शुरू हो जाएगी। छात्रों को समर्थ पोर्टल पर अपना आवेदन जमा करना होगा।उन्होंने यह भी बताया कि महाविद्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि वे समय से परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन जमा कराएं, ताकि परीक्षाएं निर्धारित समय पर शुरू हो सकें। इसके अतिरिक्त, महाविद्यालयों को 10 नवंबर तक हर हाल में पाठ्यक्रम पूरा करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।बुधवार को परीक्षा समिति की बैठक हुई, जिसमें तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की गई। परीक्षा नियंत्रक ने स्पष्ट किया कि आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही परीक्षा कार्यक्रम जारी किए जाएंगे और परीक्षाएं समय पर संपन्न कराई जाएंगी।

पंच परिवर्तन यात्रा का उद्देश्य य जन जन तक पहुंचाना - मनोज श्रीवास्तव

अयोध्या। संघ शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में भारतीय केसरिया वाहिनी द्वारा संकल्पित पंच परिवर्तन यात्रा का लखनऊ में आकर सम्पन्न हुआ।उन्होंने बताया कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य संघ के उद्देश्य को जन जन तक पहुंचाना रहा।इस मौके पर भारतीय केशरिया वाहिनी के रास्ट्रीय अध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि यह यात्रा सिर्फ लखनऊ तक ही नहीं सीमित है बल्कि आने वाले दिनों में अयोध्या सहित अन्य प्रमुख जिलों में दूसरे चरण में चलाई जाएगी जिसमें संघ के वरिष्ठ अधिकारियों पदाधिकारी के अलावा भारतीय केसरिया वहां के अहम भूमिका रहेगी इसकी रणनीति छठ पूजा के बाद तय की जाएगी।इस संबंध में भारतीय केसरिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री श्रीवास्तव ने बताया कि इस रथ यात्रा में राष्ट्रीय सेवक संघ तथा नाथ संप्रदाय का समर्थन प्राप्त रहा।जब यह रथ यात्रा लखनऊ पहुँची,तब दुबग्गा चौराहे पर वाहिनी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया।वहाँ से सैकड़ों वाहनों के साथ नगर भ्रमण आरंभ हुआ।पहला पड़ाव प्रॉमिनेंट मॉल पर हुआ।बाद मे यह यात्रा अलीगंज, जानकीपुरम, राम राम बैंक चौराहा होते हुए सेक्टर क्यू

स्थित सरस्वती विद्या मंदिर पहुँची,जहाँ यात्रा के प्रथम चरण का समापन हुआ।कार्यक्रम के दूसरे चरण में पंच परिवर्तन पर विचार संगोष्ठी आयोजित की गई।कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रभु नारायण श्रीवास्तव,पूर्व अवध प्रांत संघचालक एवं संस्थापक सदस्य,महामना मालवीय मिशन,अति विशिष्ट अतिथि संजय हर्ष,अखिल भारतीय सचिव संगठन इतिहास संकलन विभाग व पूर्व प्रांत प्रचारक,विशिष्ट अतिथियों में अशोक सिन्हा, पूर्व पीसीएस अधिकारी,वर्तमान में अवध प्रहरी के निदेशक,जे.के. सिन्हा जी,पूर्व प्रचारक व विभाग संघचालक, वर्तमान अवध प्रांत कार्यकारिणी सदस्य,प्रो. विनोद नागर, अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय सेवक संघ मौजूद रहे।कार्यक्रम की शुरुआत गुरुकुल के बालकों द्वारा "राष्ट्र रक्षा स्रोत" पाठ व दीप प्रज्वलन से हुई।संचालन अभिषेक आनंद (राष्ट्रीय संयोजक, प्रबुद्ध विभाग) ने किया।इस मौके पर भारत तिब्बत सहयोग मंच के अवध प्रांत अध्यक्ष अजित श्रीवास्तव एवं महामंत्री अंकुर सिंह,हनुमान नगर संघ चालक इंद्र कुमार वर्मा, सह संघ चालक प्रमोद कुमार, दीपक शुक्ला, संजय गुप्ता, अशोक श्रीवास्तव, वाई के. भटनागर,अरुण तिवारी (राष्ट्रीय महामंत्री, जिला प्रचारक आजाद,विशाल श्रीवास्तव,हरिश्चंद्र द्विवेदी (प्रधानाचार्य, सरस्वती विद्या मंदिर, अलीगंज सेक्टर क्यू) का विशेष योगदान रहा।

दीपोत्सव को लेकर सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा के अलावा 8 टीमों का गठन,टीमें छापा मारकर कर रही कार्यवाई

अयोध्या। दीपोत्सव को लेकर अयोध्या प्रशासन ने खाद्य सुरक्षा के मोर्चे पर पूरी तैयारी कर ली है।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिलाधिकारी ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 08 विशेष टीमें गठित की हैं।इन टीमों का उद्देश्य है कि दीपोत्सव के दौरान अयोध्या आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को सुरक्षित और शुद्ध खाद्य सामग्री ही उपलब्ध हो।इसके लिए डीएम निखिल टीकाराम फुंडे के आदेश पर पांचों तहसीलों में पांच एसडीएम के नेतृत्व में अलग–अलग टीमें बनाई गई हैं। जबकि नगर क्षेत्र में सिटी मजिस्ट्रेट की दो टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं।इसके अलावा, सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा मानिक चन्द्र सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम मुख्यालय स्तर पर गठित की गई है, जो जिलेभर में सक्रिय है।टीमों द्वारा 54 निरीक्षण, 34 जगह छापे और 76 नमूने लिए गए।दीपोत्सव से पहले खाद्य विभाग ने बड़े पैमाने पर निरीक्षण अभियान चलाया है। अब तक कुल 54 निरीक्षण किए जा चुके हैं।।जिनमें 34 स्थानों पर छापेमारी की गई है। इस दौरान खाद्य सामग्री के 76 नमूने लिए गए हैं, ताकि कोई भी मिलावटी या खराब खाद्य पदार्थ श्रद्धालुओं तक न पहुंच सके।सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा मानिक चन्द्र सिंह ने बताया कि निरीक्षण के दौरान खाद्य विभाग की टीमों ने 19,657 किलो खाद्य सामग्री बरामद की है, जिसकी कीमत 33 लाख रुपये से अधिक बताई जा रही है। इनमें से 167 किलो खराब या मिलावटी खाद्य सामग्री को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया, जिसका मूल्य 35 हजार रुपये से अधिक है। उन्होंने बताया कि दीपोत्सव के मद्देनजर यह अभियान लगातार जारी रहेगी।सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा मानिक चन्द्र सिंह ने बताया कि अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी आमद को देखते हुए अन्य जिलों से भी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की तैनाती की गई है। ये अधिकारी अयोध्या में विभिन्न स्थलों पर पहुंचकर खाद्य सामग्री की जांच करेंगे, ताकि किसी भी प्रकार की खाद्य अनियमितता की गुंजाइश न रहे। 19 और 20 अक्तूबर को बड़ी संख्या में आ रहे श्रद्धालुओं के लिहाज से सघन जांच की जाएगी।

संक्षिप्त खबरें

खाद्य सुरक्षा विभाग ने त्यौहारों के देखते हुए चलाया चेकिंग अभियान

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर सहायक आयुक्त (खाद्य) द्वितीय, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने अवगत कराया है कि आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0, लखनऊ के एवं जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में आगामी दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भाई दूज पर्वको दृष्टिगत रखते हुए मिलावटी खाद्य एवं पेय पदार्थों के भण्डारणधविक्रय पर प्रभावी रोकथाम के उद्देश्य से 08 अक्टूबर 2025 से 23 अक्टूबर 2025 तक संचालित विशेष प्रवर्तन अभियान के अन्तर्गत जनपद जौनपुर में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा किये जा रहे प्रवर्तन कार्यवाही के क्रम में खाद्य सचल दल में शामिल खाद्य सुरक्षा अधिकारीगण द्वारा 15 अक्टूबर 2025 को जनपद जौनुपर के विभिन्न बाजारों में स्थित अलग–अलग खाद्य प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थ खोया का 6 नमूना, बूंदी लड्डू का 1 नमूना, पेड़ा का 1 नमूना, पनीर का 1 नमूना एवं छेना मिठाई का 1 नमूना संग्रहीत किया गया है। इस प्रकार विभिन्न खाद्य पदार्थों का कुल–10 नमूना संग्रहीत करते हुए जांच हेतु खाद्य विश्लेषक को प्रेषित किया गया। निरीक्षण के दौरान खाद्य प्रतिष्ठानों में साफ–सफाई इत्यादि की कमी पाये जाने पर कुल–06 खाद्य प्रतिष्ठानों को सुधार नोटिस जारी किया गया। इस प्रकार 08 अक्टूबर 2025 से 15 अक्टूबर 2025 तक जनपद जौनपुर के कुल–97 विभिन्न प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण करते हुए विभिन्न खाद्य पदार्थों के कुल–54 नमूनें संग्रहीत कर नियमानुसार जांच हेतु खाद्य विश्लेषक को प्रेषित किया गया। निरीक्षण के दौरान खाद्य प्रतिष्ठानों में साफ–सफाई इत्यादि की कमी पाये जाने पर कुल–33 खाद्य प्रतिष्ठानों को सुधार नोटिस जारी किया गया एवं अस्वच्छकरध्मानव उपभोग हेतु अनुपयुक्त पाये जाने पर दुग्ध उत्पाद से बनी विभिन्न मिठाईयां कुल–309 कि.ग्रा. (अनुमानित मूल्य रू0 66050) को मौके पर नियमानुसार विनष्ट कराया गया तथा मिलावट के सन्देह के आधार पर विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ कुल–1100 कि.ग्रा. अनुमानित मूल्य रू0 129000) को नियमानुसार जब्त किया गया।

राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता मे टाप कर अभिश्री श्रीवास्तव ने किया जिले का नाम रोशन

अयोध्या। पत्रकार राजेश श्रीवास्तव के ममेरे भाई व जिले के प्रसिद्ध नाक,कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव तथा डाक्टर रिद्धिमा श्रीवास्तव की पुत्री अभिश्री श्रीवास्तव ने बोब वंडरकिड 2025 राष्ट्रीय स्तर हुए प्रतियोगिता मे राष्ट्रीय स्तर पर टाप कर अयोध्या जिले का नाम रोशन किया है।बताते चलें कि अभिश्री शहर के शक्तिनगर कॉलोनी निवासी डॉ गौरव की पुत्री जिले के प्रतिष्ठित स्कूल जिंगेल बेल स्कूल की कक्षा एक की छात्रा है।इस सफलता पर उसे प्रमाण पत्र के साथ–साथ 1500 रुपये का चेक भी प्राप्त हुआ।बताते चले कि अभिश्री श्रीवास्तव शुरू से ही अनुशासन के साथ–साथ मेधावी छात्रा भी है।उनके इस सफलता पर जिंगल बेल स्कूल के प्रधानाचार्य, शिक्षक,कर्मचारियों के साथ–साथ कैलाश लाल श्रीवास्तव,बालेश श्रीवास्तव,इंजीनियर सौरभ श्रीवास्तव आकांक्षा श्रीवास्तव,जिला व पुलिस प्रशासन के अधिकारियों,पत्रकारों के साथ साथ आसपास के लोगों ने शुभकामनाएं दिया।

स्व. अर्जुन सिंह यादव ने अपना संपूर्ण जीवन गरीबों, किसानों, मजदूरों शोषितों के अधिकारों की लड़ाई में समर्पित किया

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,जिले की शान, गरीबों और मजलूमों के मसीहा, पूर्व विधायक एवं पूर्व सांसद श्रद्धेय स्व. अर्जुन सिंह यादव जी की 27वीं पुण्यतिथि के अवसर पर एक सर्वदलीय श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता के. पी. सोनकर, राष्ट्रीय महासचिव, भारत मुक्ति पार्टी ने की तथा संचालन एडवोकेट राम कृपाल यादव (आंबेडकरवादी) द्वारा किया गया। इस अवसर पर जिले के विभिन्न राजनैतिक दलों एवं सामाजिक संगठनों के सम्मानित व्यक्तित्वों ने पहुँचकर स्व. अर्जुन सिंह यादव जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके द्वारा किए गए संघर्षों, जनसेवा और सामाजिक न्याय के कार्यों को याद किया। श्रद्धांजलि सभा में विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और बुद्धिजीवियों ने एक साथ आकर स्व. अर्जुन सिंह यादव जी के संघर्षमय जीवन, सामाजिक चेतना और जनसेवा के कार्यों को याद किया। सभी वक्ताओं ने कहा कि स्व. अर्जुन सिंह यादव जी ने अपना संपूर्ण जीवन गरीबों, किसानों, मजदूरों और शोषितों के अधिकारों की लड़ाई में समर्पित किया। वे एक ऐसे जननेता थे जिन्होंने सदैव सच्चाई, ईमानदारी और समाजवाद के मार्ग पर चलकर जनहित की राजनीति की। उनके योगदान को आने वाली पीढ़ियाँ सदैव याद रखेंगी। आशाराम यादव पूर्व अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा आयोग, अधिवक्ता वीरेंद्र प्रजापति, ओम नाथ बिंद प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी युवजन सभा, कामरेड विजय यादव ऊदल, उमेंद्र यादव प्रधान नरौली,आनंद गुप्ता जिला अध्यक्ष लोहिया वाहिनी, डॉ शिवजीत यादव पूर्व जिलाअध्यक्ष समाजवादी युवजन सभा, राजेश दुबे, अजीत कुमार गौतम, चंदन सिंह, राजकुमार वकील इत्यादि उपस्थित रहें। कार्यक्रम के अंत में सभी ने दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धेय अर्जुन सिंह यादव जी की आत्मा की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना की और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया।

संक्षिप्त खबरें

आईजी प्रवीण कुमार ने पैदल गैस कर स्थानीय लोगों को कराया सुरक्षा का एहसास

अयोध्या। दीपावली सहित आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क दिखाई दे रहा है इसी कड़ी में बुधवार की शाम खुद आईजी रेंज अयोध्या प्रवीण कुमार ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ शहर के रिकॉर्ड गण चौराहे से चौक तक पैदल गस्त किया इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों को सुरक्षा के प्रति एहसास कराया की पुलिस दीपावली सहित अन्य त्योहारों पर आपके साथ है आप इस त्यौहार को खुशी–खुशी मनाएं। इस दौरान आईजी प्रवीण कुमार ने शहर वासियों के साथ व्यापारियों व आम जनता को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। उन्होंने दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की अपील की।महिलाओं से बातचीत कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया।इस दौरान एसपी सिटी चक्रपाणि त्रिपाठी,सीओ सिटी शैलेंद्र सिंह, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर अश्वनी पांडे, थानाध्यक्ष आशा शुक्ला व अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद थे।

डीएम ने मेडिकल कॉलेज का किया औचक निरीक्षण अवशेष विद्युत कार्य पर जताई नाराजगी

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर । जिलाधिकारी डॉ0 दिनेश चंद्र के द्वारा उमानाथ सिंह स्वशासी मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल भवन में जाकर नामित कार्यदायी संस्था द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यो के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की, अभी भी अवशेष विद्युत तथा सिविल संबंधी कार्यों पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने कार्यदायी संस्था के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देशित किया कि इलेक्ट्रिकल के अवशेष कार्यों को 15 नवंबर 2025 तक और सिविल के अवशेष कार्य को भी शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण करले अन्यथा की दशा में कार्यदायी संस्था के विरुद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। जिलाधिकारी के द्वारा मेडिकल कालेज में मरीजों को दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं और दवाओं की उपलब्धता सहित अन्य विषयों पर विस्तार से जानकारी प्राप्त की गयी। उन्होंने निर्देशित किया कि ईलाज कराने आये मरीजों का अच्छे से ईलाज किया जाए। इस अवसर पर प्राचार्य आरबी कमल, सीएमएस डा0 जाफरी, डा0 आशीष यादव, डा0 रूचिरा सेठी सहित अन्य उपस्थित रहे।

स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए - रमेश सिंह

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,। बीआरपी इंटर कॉलेज के मैदान में जनपद स्तरीय यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेला का आयोजन किया गया है। जहाँ एक तरफ लोगो के द्वारा स्वदेशी उत्पादों को पसंद किया जा रहा है वही दूसरी ओर उत्पादों की बिक्री भी बढ़ती जा रही है, लोगो का पसंद बनता जा रहा हस्तनिर्मित उत्पाद है।ज्यादातर स्वदेशी उत्पादों में गाय के गोबर के बने दीये, मिट्टी के सामानों, सजावटी उत्पादों और हाथों से बने स्वादिष्ट अचार, मुरब्बा आदि को पसंद किया जा रहा है इसके साथ ही घरों को स्वच्छ रखने के उत्पादों जैसे हैंडवास, फिनायल, ट्वायलेट क्लीनर सहित अन्य सामग्री को भी ग्राहको द्वारा पसंद किया जा रहा है। गुरुवार को स्वदेशी मेले के आठवें दिन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक विधायक शाहगंज रमेश सिंह, विशिष्ट अतिथि अजीत प्रताप सिंह, जिलाधिकारी डा0 दिनेश चन्द्र सहित अन्य प्रबुद्धजनों के द्वारा द्वीप प्रज्जवलित कर और फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। मुख्य अतिथि के द्वारा विभिन्न विभागों के द्वारा लगाए गए स्टालों का अवलोकन करते हुए खादी के वस्त्र, साड़ी, अचार, मिट्टी के दीये, हस्तनिर्मित दरवाजा तोरन सहित अन्य उत्पादों की खरीददारी करते हुए अन्य लोगों को भी स्वदेशी उत्पादों को प्रयोग में लाने के लिए प्रेरित किया गया। विधायक के द्वारा किसान बंशराज को कृषि विभाग के द्वारा अनुदानित ट्रैक्टर की सांकेतिक चाभी और सीएम युवा उद्यमी के लाभार्थी अमरजीत सिंह को सांकेतिक चेक प्रदान किया गया। मुख्य अतिथि विधायक रमेश मिश्रा ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्रीजी और मुख्यमंत्री के 2047 में विकसित भारत की संकल्पना तभी साकार होगी जब प्रदेश, जिला, तहसील, और ग्राम पंचायते, विकसित होगी जिसके लिए आवश्यक होगा कि स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को बढावा दिया जाए। युवाओं का आत्मनिर्भर बनाने के उददेश्य में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना की शुरूआत की गयी जिससे युवा अपने जनपद में ही स्वरोजगार शुरू कर सके। उन्होने स्वदेशी मेले में बिक्री हेतु वस्तुओं के पैकेजिंग की सराहना की। विधायक ने लोगों से अपील किया गया कि स्वदेशी वस्तुओं की खरीददारी कर देश को विकसित बनाने में अपना योगदान दे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हर वह चीज स्वदेशी है जिसमें किसी भारतीय का पसीना और मेहनत शामिल है। उन्होंने देशवासियों से "वोकल फॉर लोकल" का मंत्र अपनाकर "मेक इन इंडिया" उत्पादों को बढ़ावा देने का संकल्प लेने का आग्रह किया। जिलाधिकारी ने कहा कि 'स्वदेशी' अभियान को बढ़ावा देने के लिए इस मेले का आयोजन किया गया है। इनका उददेश्य लोगों को विदेशी सामानों की जगह अपने देश अपने जनपद में बने सामान खरीदने के लिए प्रेरित करना है। शासन की मंशा है कि लोग अधिक से अधिक संख्या में स्वदेशी उत्पादों की खरीददारी करके भारतीय कारीगरों और उद्योगों को सपोर्ट करें। जब हम अपने देश और जनपद का सामान खरीदते हैं, तो यह पैसा देश और अपने जनपद में ही रहता है ।

बरामदे से सड़क पर खींचकर किए गए वार, मची अफरातफरी

पीलीभीत, (संवाददाता)। अधिवक्ता ओमपाल पर हत्या के इरादे से योजनाबद्ध तरीके से हमला किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हमलावर कचहरी परिसर के पीछे वाले हिस्से से आए थे और ओमपाल को बरामदे से खींचकर सड़क पर लाने के बाद ताबड़तोड़ प्रहार शुरू कर दिए। पुलिसकर्मियों की हिम्मत और तत्परता से अधिवक्ता की जान बची। अधिवक्ता पर बांके से हमला देख कचहरी में सिविल बार एसोसिएशन के प्रांगण में अफरातफरी मच गई। हमले ने कचहरी की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आरोपी खुलेआम धारदार हथियार लेकर अधिवक्ताओं के बिस्तर तक पहुंच गए और ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। घटना के बाद कचहरी पहुंचे एसपी अभिषेक यादव और सीओ सिटी दीपक चतुर्वेदी ने सुरक्षा व्यवस्था की जांच की। उन्होंने अधिवक्ताओं से बातचीत कर सुरक्षा संबंधी सुझाव सुने। अधिवक्ताओं ने कचहरी के पिछले हिस्से से बेरोकटोक आवाजाही की शिकायत की, इस पर एसपी ने वहां ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्य द्वार पर बिना चेकिंग किसी को प्रवेश न देने की सख्त हिदायत दी। अधिवक्ताओं के सुझाव पर एसपी ने आने–जाने के लिए अलग–अलग चेकिंग गेट लगवाने का आश्वासन भी दिया। अधिवक्ताओं ने एसपी से यह भी कहा कि यदि पुलिसकर्मी समय रहते सक्रिय न होते तो कचहरी परिसर में बड़ी घटना हो सकती थी। उन्होंने मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों का सम्मान करने की बात भी कही। अधिवक्ता पर हमले के सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिल गए हैं। इसमें हमलावर बरामदे में घुसकर अधिवक्ता पर हमला करते दिखते हैं और बाद में उन्हें सड़क पर खींच लाते हैं। डर और दहशत के बीच कुछ लोग आगे बढ़ने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन रुक जाते हैं। अगस्त 2022 में ग्राम बरखड़ी में पूर्व प्रधान कृष्णपाल की हत्या कर दी गई थी। बताया गया कि यह घटना प्रधानी चुनाव की रंजिश का नतीजा थी। वर्ष 2016 में कृष्णपाल प्रधान बने थे, जबकि अधिवक्ता ओमपाल के समर्थित प्रत्याशी को हार मिली थी। वर्ष 2021 के चुनाव में ओमपाल पक्ष की प्रत्याशी की जीत के बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया था। वर्ष 2022 में 17 अगस्त को हुए संघर्ष में कृष्णपाल गंभीर रूप से घायल हुए और 23 अगस्त की रात उनकी मौत हो गई। इस मामले में कृष्णपाल के भाई जसपाल सिंह ने ओमपाल, उनके पुत्र दिनेश, भतीजे विजय और हरिपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने तब ओमपाल को जेल भेजा था और मामला वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है। घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। कचहरी के पीछे का भाग खुला है। आरोपी उसे क्षेत्र से पहुंचे थे। उस भाग को भी चेकिंग प्वाइंट में शामिल कर दिया गया है। इसके अलावा अधिवक्ताओं से बातचीत कर जानकारी की गई। सुरक्षा को लेकर अन्य जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इस पर अमल भी शुरू करा दिया गया है। दिनदहाड़े अधिवक्ता पर जानलेवा हमला दुर्भाग्यपूर्ण है। अधिवक्ताओं की सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक
श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव
मो0 – 7007415808, 9415034002
Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबंधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।